प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

आदेश सुरक्षित किया गया :19.12.2025

आदेश पारित किया गया : 02.01.2026

आदेश अपलोड किया गया : 02.01.2026

विविध दाण्डिक प्रकरण सं 8224/2025

1 – चैतन्य बघेल पिता श्री भूपेश बघेल उम्र लगभग 38 वर्ष निवासी 1/7 मानसरोवर परिसर, भिलाई, दुर्ग छत्तीसगढ़।(वर्तमान में सेंट्रल जेल, रायपुर (छ.ग.) में न्यायिक अभिरक्षा में है)

---आवेदक

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) / भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय के द्वारा , जय जवान पेट्रोल पंप के सामने,तेलीबांधा, रायपुर छत्तीसगढ़ – 492001

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक हेतु :	:	श्री एन.हरिहरन, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री मयंक जैन, श्री मधुर जैन, श्री अर्पित गोयल और श्री दीपक जैन अधिवक्ता, श्री हर्षवर्द्धन परगनिहा और सुश्री मनुभा शंकर, अधिवक्ता की सहायता से वीसी के माध्यम से।
उत्तरवादी/राज्य हेतु :	:	श्री महेश जेठमलानी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री रवि शर्मा, अधिवक्ता द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहायता प्रदान की गई, और डॉ. सौरभ पांडे, उप महाधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदान की गई।

(माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश)

सी. ए. वी. आदेश

1. यह आवेदन आवेदक द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ईओडब्ल्यू/एसीबी, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 17.01.2024 को दर्ज एफआईआर संख्या 04/2024 के संबंध में नियमित जमानत पर रिहाई की मांग की गई है (जिसे आगे "अनावेदक" कहा गया है) जिसमें आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120–बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 12 के तहत अपराधों का आरोप है।वर्तमान जमानत याचिका पर निर्णय लेने के सीमित और विशिष्ट उद्देश्य के लिए, यह न्यायालय प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों पर ध्यान देना उचित समझता है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :

2. एफआईआर और इस न्यायालय के समक्ष मौजूद अभिलेखों में अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त प्रकरण यह है कि ईडी के दिनांक 11.07.2023 के पत्र के माध्यम से धारा 66(2) पीएमएलए के तहत आरोप लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ में लाइसेंस प्राप्त सरकारी दुकानों के माध्यम से अवैध शराब के निर्माण/विक्रय में शामिल एक बड़े गिरोह ने 2019–2023 के दौरान भारी मात्रा में आय अर्जित की, जिसे आबकारी अधिकारियों, नौकरशाहों, शराब बनाने वालों और राजनीतिक पदाधिकारियों के बीच वितरित किया गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है।यह उल्लेखनीय है कि एफआईआर में आवेदक का नाम नहीं था। अन्वेषण 21 महीनों तक चली, दिनांक 01.07.2024 की आरोप पत्र संख्या 03/2024 में 4 आरोपियों को आरोपित किया गया; इसमें कहा गया है कि "आगे की अन्वेषण जारी है।"क्रमानुसार पांच पूरक आरोपपत्र दाखिल किए गए:27.09.2024, 18.11.2024, 30.06.2025, 07.07.2025 और 26.08.2025 – इनमें से किसी में भी आवेदक को आरोपित नहीं किया गया, हालांकि संदर्भ उपयुक्त थे।कुल 51 अभियुक्तगण को नामजद किया गया और बिना गिरफ्तारी के 29 आरोपपत्र दाखिल किए गए।ईडी ने इस एफआईआर के आधार पर दिनांक 11.04.2024 को ईसीआईआर आरपीजेडओ/04/2024 दर्ज किया और आवेदक के परिसर में तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप 18.07.2025 को गिरफ्तारी हुई।आवेदक ने इसे सीआरएमपी संख्या 2506/2025 में चुनौती दी।ईडी ने 15.08.2025 को अभियोजन परिवाद दर्ज की।

3. 60 दिनों की अभिरक्षा अवधि समाप्त होने के बाद, ईडी ने विशेष न्यायालय से दो दिन की पूछताछ की अनुमति मांगी, जिसे 12.09.2025 को स्वीकार कर लिया गया था।ईओडब्ल्यू ने 15.09.2025 को तत्काल उत्पादन वारंट के लिए आवेदन किया।प्रस्तुत किये जाने पर,ईओडब्ल्यू ने उसी दिन गिरफ्तारी के लिए आवेदन दायर किया, जिसे ग्राह्य योग्य न होने के कारण खारिज कर दिया गया तथा उसे इस बात की स्वतंत्रता दी गयी की वह सत्र न्यायलय की शरण में जाये ।सत्र न्यायालय ने याचिका संख्या 2762/2025 की जमानत याचिका 22.09.2025 को खारिज कर दी तथा तत्पश्चात् 24.09.2025 को भी इसे खारिज कर दिया गया।इस न्यायालय द्वारा अस्वीकृति के बावजूद, ईओडब्ल्यू ने 24.09.2025 को आवेदक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पेशी वारंट गिरफ्तारी को अधिकृत नहीं करता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विशेष न्यायालय ने आरोप लगाया कि आवेदक ने उत्पाद शुल्क की राशि को गुप्त माध्यमों से अपनी निर्माण कंपनी को हस्तांतरित किया।कोई वसूली प्रभावित नहीं हुई; रिमांड के बाद कोई और पूछताछ नहीं की गई। इसके बाद आवेदक ने रायपुर स्थित विशेष न्यायालय (पुलिस अधिनियम) में नियमित जमानत के लिए अर्जी दी, जिसे 8.10.2025 को खारिज कर दिया गया।अतः,वर्तमान जमानत याचिका दायर की गई है।इस न्यायालय द्वारा 24.09.2025 को आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद, ईओडब्ल्यू/एसीबी ने उसी दिन (24.09.2025) आवेदक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, जबकि पहले जारी किए गए उत्पादन वारंट में ऐसी गिरफ्तारी को न तो अधिकृत किया गया था और न ही इसका कोई प्रावधान था।अनावेदक ने तुरंत रायपुर स्थित माननीय विशेष न्यायालय (पी सी अधिनियम) के समक्ष पुलिस अभिरक्षा हेतु 24.09.2025 से 06.10.2025 तक (पूरे 12 दिन) निरोध याचिका दायर की।उक्त पुनर्विचार याचिका में अस्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया था कि आवेदक ने "उत्पाद शुल्क अपराध की आय से धन की व्यवस्था की और विभिन्न चैनलों के माध्यम से इसकी डिलीवरी का निर्देश दिया", अंततः उक्त धनराशि का उपयोग अपनी निर्माण फर्म की परियोजनाओं में किया था।माननीय विशेष न्यायालय ने रिमांड आवेदन स्वीकार करते हुए अनुरोध के अनुसार पुलिस अभिरक्षा प्रदान की गयी।हालांकि, पूरी रिमांड अवधि (24.09.2025 से 06.10.2025) के दौरान:आवेदक या उसके परिसर से किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं की गई थी।12.09.2025 को प्रारंभिक 2 घंटे की पूछताछ के बाद कोई और पूछताछ नहीं की गई। ईओडब्ल्यू द्वारा आवेदक के आवासीय/व्यावसायिक परिसर में कोई तलाशी नहीं ली गई (जो कि ईडी द्वारा 18.07.2025 को की गई तलाशी के बिल्कुल विपरीत है)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इसके बाद, आवेदक ने रायपुर स्थित माननीय विशेष न्यायालय (पी. सी अधिनियम) के समक्ष धारा 483 बीएनएसएस के तहत नियमित जमानत याचिका दायर की, जिसे दिनांक 08.10.2025 के विस्तृत आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।यही आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई वर्तमान जमानत याचिका है।

<u>आवेदक की ओर से प्रस्तुतियाँ :</u>

6. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उचित रूप से प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय को प्रकरण के अनूठे तथ्यों और परिस्थितियों की ओर आकर्षित करते हुए, उन्होंने अत्यंत सम्मानपूर्वक और दृढ़तापूर्वक निम्नलिखित निवेदन किया:

I. आवेदक की गिरफ्तारी स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण, मनमानी है और वैधानिक उपायों को विफल करने के लिए अभिरक्षा को बार–बार बढ़ाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

––विधि की प्रक्रिया का घोर उल्लंघन, तत्काल रिहाई की मांग।

7. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहरन ने प्रस्तुत किया कि यह कोई साधारण जमानत याचिका नहीं है; यह आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा गिरफ्तारी शक्तियों के घोर दुरुपयोग के विरुद्ध एक स्पष्ट आह्वान है, जिसका उद्देश्य उन प्रकरण में कारावास को लंबा खींचना है जहां अन्वेषण लगभग पूरी हो चुकी है।

इस अभियोग के आधारभूत दस्तावेज, दिनांक 17.01.2024 की एफआईआर में आवेदक का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है।पूरे 21 महीनों की अन्वेषण के बावजूद, जिसके दौरान 01.07.2024, 27.09.2024, 18.11.2024, 30.06.2025, 07.07.2025 और 26.08.2025 को छह आरोपपत्र (मुख्य + पांच पूरक) सावधानीपूर्वक दायर किए गए, आवेदक को उन सभी प्रकरण में आरोपी के रूप में स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया था।इससे भी अधिक निंदनीय बात यह है कि आवेदक के विरुद्ध विशिष्ट आरोपों का उल्लेख 01.07.2024 की मुख्य आरोपपत्र के पृष्ठ 239 पर ही मिलता है – फिर भी 15 से अधिक महीनों तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और इस सुनियोजित विलंब की समयरेखा को देखते हुए:ईओडब्ल्यू को जुलाई 2024 से ही आवेदक की कथित भूमिका की पूरी जानकारी थी, फिर भी उसने 24.09.2025 का सटीक समय चुना – ठीक उसी समय जब इस न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और आवेदक की ईडी अभिरक्षा से वैधानिक रिहाई की अंतिम तिथि नजदीक थी (उसे ईडी ने 18.07.2025 को गिरफ्तार किया था, और वह धारा 167(2) बीएनएसएस के तहत 60 दिन की डिफ़ॉल्ट जमानत अवधि के करीब था)।यह "बीमा गिरफ्तारी" की सटीक परिभाषा है – संवैधानिक उपायों को विफल करने की एक दुर्भावनापूर्ण रणनीति। धारा 41ए बीएनएसएस के तहत कोई समन जारी नहीं किया गया था।ईओडब्ल्यू द्वारा आवेदक के परिसर में कोई तलाशी नहीं ली गई (ईडी के विपरीत, जिसने 18.07.2025 को तलाशी ली थी और कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई थी)।किसी भी प्रकार की पूछताछ की आवश्यकता नहीं पड़ी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

– वास्तव में, जब अंततः 2 दिनों (12–13.09.2025) के लिए अनुमति मांगी गई, तो पहले दिन केवल 2 घंटे ही पर्याप्त थे, और दूसरे दिन को सुविधाजनक रूप से छोड़ दिया गया था।कार्यपालिका की मनमानी से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरा होने पर इस न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए।जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक प्रकरण **जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1994) 4 एससीसी 260 (कंडिका 8–10)** में यह अभिनिर्धारित किया है:

8. मानवाधिकारों का दायरा बढ़ रहा है।साथ ही, अपराध दर भी बढ़ रही है।हाल ही में, इस न्यायालय को अंधाधुंध गिरफ्तारियों के कारण मानवाधिकारों के उल्लंघन के परिवाद प्राप्त हुई हैं।हम इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएँ?9. इस दिशा में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।गिरफ्तारी का विधि एक ओर व्यक्तिगत अधिकारों, स्वतंत्रता और विशेषाधिकारों और दूसरी ओर व्यक्तिगत कर्तव्यों, दायित्वों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित करने कि विधि है; यह एक व्यक्ति के अधिकारों, स्वतंत्रता और विशेषाधिकारों और सामूहिक रूप से व्यक्तियों के अधिकारों, स्वतंत्रता और विशेषाधिकारों का मूल्यांकन और संतुलन स्थापित करने कि विधि है; यह निर्धारित करने कि विधि है कि क्या वांछित है और किस पर जोर देना है; यह निर्धारित करने कि विधि है कि अपराधी पहले आता है या समाज, विधि तोड़ने वाला पहले आता है या विधि का पालन करने वाला; यह उस चुनौती का सामना करने कि विधि है जिसका सामना न्यायमूर्ति कार्डोज़ो ने इतनी स्पष्टता से किया था जब उन्होंने व्यक्तिगत अधिकारों और समाज के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने के समान कार्य से जूझते हुए बुद्धिमानी से यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बहिष्करण नियम त्रुटिपूर्ण विधि थी,

समाज पहले आता है, और अपराधी को इसलिए मुक्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि सिपाही ने त्रुटि की थी। पीपल बनाम डिफोर 1 में न्यायमूर्ति कार्डोजो ने कहाः

"प्रश्न यह है कि क्या व्यक्ति की सुरक्षा के बदले समाज की सुरक्षा में भारी नुकसान तो नहीं होगा?एक तरफ अपराध पर अंकुश लगाने की सामाजिक आवश्यकता है।दूसरी तरफ, सत्ता के दुरुपयोग से विधि का उल्लंघन न होने देने की सामाजिक आवश्यकता है।किसी भी विकल्प में खतरे हैं।एडम्स प्रकरण (पीपल्स बनाम एडम्स 2) का नियम परस्पर विरोधी हितों के बीच संतुलन स्थापित करता है।हमें इसे तब तक विधि मानना होगा जब तक कि सरकार के वे अंग जिनके द्वारा सामान्यतः सार्वजनिक नीति में परिवर्तन किया जाता है, न्यायालय को यह सूचना न दे दें कि परिवर्तन हो चुका है।

10. फ्राइड री3 में विद्वान न्यायाधीश हैंड का बयान भी इसी तरह का है:

"पुलिस और अन्य विधि लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से व्यक्ति की सुरक्षा वास्तव में एक स्वतंत्र समाज में एक प्रमुख हित है; परंतु अपराध का प्रभावी अभियोजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, एक ऐसा हित जिसे कभी-कभी भुला दिया जाता है।"पूर्णता असंभव है; अन्य मानवीय संस्थाओं की तरह आपराधिक कार्यवाही भी एक समझौता ही होती है।किसी राष्ट्र की सभ्यता की गुणवत्ता का आकलन काफी हद तक आपराधिक विधि के प्रवर्तन में अपनाए जाने वाले तरीकों से किया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. किसी पुलिस अधिकारी के लिए गिरफ्तारी करना वैध होने मात्र से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती हैगिरफ्तारी करने की शक्ति का होना एक बात है और उसका प्रयोग उचित ठहराना बिल्कुल अलग बात है।पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी करने की शक्ति के अलावा, गिरफ्तारी को उचित ठहराने में सक्षम होना चाहिए।हाल ही में,अरविंद केजरीवाल बनाम सीबीआई, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 2550 प्रकरण में,सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय अभिनिर्धारित किया :

"31. इसी संदर्भ में, धारा 41(1)(ख) की भाषा इस प्रकार है:

"41. पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है।(1) कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है—
(ख) जिसके विरुद्ध उचित परिवाद की गई हो, या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो, या यह उचित संदेह हो कि उसने संज्ञेय अपराध किया है जिसके लिए कारावास का दंड सात वर्ष से कम या सात वर्ष तक हो सकती है, चाहे जुर्माने के साथ हो या बिना जुर्माने के, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात्::----
(i) पुलिस अधिकारी को ऐसे परिवाद, सूचना या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है;
(ii) पुलिस अधिकारी संतुष्ट है कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है—
(क) ऐसे व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकने के लिए; या(ख) अपराध की उचित अन्वेषण हेतु; या(ग) ऐसे व्यक्ति को अपराध के साक्ष्य को लुप्त करने या किसी भी प्रकार से उसमें छेड़छाड़ करने से रोकना;

या (घ) ऐसे व्यक्ति को प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन करने से रोकना ताकि वह न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से हतोत्साहित हो जाए; या(ड) चूंकि जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, और पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।परंतु कि पुलिस अधिकारी उन सभी प्रकरण में, जहां इस उपधारा के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, गिरफ्तारी न करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।32. सीआरपीसी की धारा 41(1)(बी)**(ii)** में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया है कि इस प्रावधान के तहत गिरफ्तारी किसी परिवाद या विश्वसनीय सूचना के आधार पर की जा सकती है कि किसी व्यक्ति ने सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, जिसमें जुर्माना हो भी सकता है और नहीं भी। हालाँकि, ऐसी गिरफ्तारी उपधारा (क) से (ड) में उल्लिखित विशिष्ट शर्तों की संतुष्टि के अधीन ही की जानी चाहिए।धारा 41(1)(बी)**(ii)** की कठोरता की इस न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार (उपरोक्त) में व्यापक रूप से परीक्षा की गई है, जहां यह देखा गया था कि:

" 7.1.उपरोक्त प्रावधान को सीधे तौर पर पढ़ने से यह स्पष्ट है कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर सात वर्ष से कम या सात वर्ष तक की कारावास का दंड (जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के) का आरोप है, पुलिस अधिकारी द्वारा केवल इस बात से संतुष्ट होने पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है कि उस व्यक्ति ने उपर्युक्त दंडनीय अपराध किया है।गिरफ्तारी से पहले, पुलिस अधिकारी को ऐसे प्रकरण में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऐसी गिरफ्तारी किसी अन्य अपराध को करने से रोकने के लिए; या प्रकरण की उचित जांच के लिए; या आरोपी को अपराध के साक्ष्य को गायब करने से रोकने के लिए; या किसी भी तरह से साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए; या किसी साक्षी को प्रलोभन, धमकी या वादा करके उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए; या जब तक ऐसे आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।ये निष्कर्ष हैं, जिन पर तथ्यों के आधार पर पहुंचा जा सकता है।

7.2.विधि के अनुसार, पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी करते समय उन तथ्यों को बताना और उन कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना अनिवार्य है जिनके आधार पर वह उपरोक्त प्रावधानों में से किसी के अंतर्गत आने वाले किसी निष्कर्ष पर पहुंचा है।विधि के अनुसार पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तारी न करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना भी अनिवार्य है।

7.3.मूल रूप से, गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारी को स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए: गिरफ्तारी क्यों? क्या यह वास्तव में आवश्यक है?यह किस उद्देश्य की पूर्ति करेगा?इससे क्या उद्देश्य प्राप्त होगा?उपर्युक्त शर्तों के पूरा होने पर ही गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।संक्षेप में, गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारियों के पास सूचना और साक्ष्य के आधार पर यह मानने का कारण होना चाहिए कि आरोपी ने अपराध किया है।इसके अलावा, पुलिस अधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की धारा 41 के खंड (1) के उपखंड (क) से (ङ) में उल्लिखित एक या एक से अधिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक है।

33. इस टिप्पणी को देखते हुए, यद्यपि धारा 41(1)(ख) के सिद्धांतों के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क सही हैं, फिर भी यह प्रावधान वर्तमान परिस्थिति पर लागू नहीं होता है।यह एक ऐसा प्रकरण है जहां न्यायालय ने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता की गिरफ्तारी को मंजूरी दी, जिसके लिए आवश्यक वारंट जारी किया गया था।इस प्रकार, गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के लिए गिरफ्तारी के वैध कारणों के अस्तित्व के संबंध में कोई राय बनाने का अवसर नहीं था।सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा कार्य किए जाने के कारण, पुलिस अधिकारी से न्यायालय के आदेश पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।"

9. इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि तथ्यों की जटिलता और जाल तथा अभिलेख पर मौजूद सामग्री के कारण, कथित षड़यंत्र में अपीलकर्ता की भूमिका को व्यापक रूप से निर्धारित करना महत्वपूर्ण था और उसके बाद ही उसकी जमानत की पात्रता का निर्णय करना चाहिए।यह देखा गया है किः

38. भारत में जमानत न्यायशास्त्र का विकास इस बात को रेखांकित करता है कि 'जमानत का विवाद्यक स्वतंत्रता, न्याय, सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक खजाने पर भार का विवाद्यक है, ये सभी इस बात पर जोर देते हैं कि जमानत का एक विकसित न्यायशास्त्र है जो कि सामाजिक रूप से संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है'।

4. इस सिद्धांत को आगे विस्तारित करते हुए यह स्थापित किया गया है कि विचारण की प्रतीक्षा में किसी आरोपी व्यक्ति को लंबे समय तक कारावास में रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अन्यायपूर्ण हनन है।इस न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (इसके बाद 'यूएपीए') के प्रावधानों के तहत एक प्रकरण में भी इस सिद्धांत का विस्तार किया है, भले ही उस अधिनियम की धारा 43–डी (5) में वैधानिक प्रतिबंध निहित हो, यह निर्धारित करते हुए कि जमानत देने के खिलाफ विधायी नीति तब ध्वस्त हो जाएगी जब उचित समय के भीतर परीक्षण पूरा होने की कोई संभावना नहीं है।

5. न्यायालय विचाराधीन कैदी के प्रति लचीला दृष्टिकोण अपनाते हुए सदैव 'स्वतंत्रता' की ओर झुकेंगे, सिवाय उन प्रकरण के जब ऐसे व्यक्ति की रिहाई से सामाजिक आकांक्षाओं को ठेस पहुँचने, विचारण में बाधा आने या विधि के शासन के अभिन्न अंग माने जाने वाली आपराधिक न्याय प्रणाली की छवि खराब होने की संभावना हो।

39. इन कार्यवाही के दौरान यह प्रस्तुत किया गया कि एफआईआर 17.08.2022 को दर्ज की गई थी और तब से आरोपपत्र के साथ चार पूरक आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं।चौथी पूरक आरोपपत्र 29.07.2024 को दाखिल की गई थी और हमें सूचित किया गया है कि विचारण न्यायालय ने इसका संज्ञान ले लिया है। इसके अतिरिक्त, सत्रह आरोपियों के नाम दर्ज किए गए हैं, 224 व्यक्तियों को साक्षी के रूप में पहचाना गया है,

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और भौतिक और डिजिटल दोनों प्रकार के व्यापक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं।इन कारकों से संकेत मिलता है कि निकट भविष्य में विचारण की समाप्ति की संभावना नहीं है।

40. हमारे विचार में, यद्यपि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी की प्रक्रिया वैधता और अनुपालन के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करती है, फिर भी विचारण की सुनवाई तक लंबी अवधि के लिए कारावास स्थापित विधिक सिद्धांतों और अपीलकर्ता के संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। अपीलकर्ता को इसी न्यायालय द्वारा ईडी प्रकरण में 10.05.2024 और 12.07.2024 को अंतरिम जमानत दी गई थी, जो समान तथ्यों पर आधारित है।इसके अतिरिक्त, सीबीआई और ईडी दोनों प्रकरण में कई सह–आरोपियों को भी विचारण न्यायालय, उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा अलग–अलग कार्यवाही में जमानत दी जा चुकी है।

41. जहां तक अपीलकर्ता द्वारा विचारण के परिणाम को प्रभावित करने की आशंका का सवाल है, ऐसा प्रतीत होता है कि सीबीआई के निराकण से संबंधित सभी साक्ष्य और सामग्री पहले से ही उनके कब्जे में हैं, जिससे अपीलकर्ता द्वारा छेड़छाड़ की संभावना नगण्य हो जाती है।इसी प्रकार, अपीलकर्ता की स्थिति और समाज में उसकी जड़ों को देखते हुए, उसके देश से भाग जाने की आशंका को मानने का कोई वैध कारण नहीं दिखता है।किसी भी प्रकरण में, सीबीआई की आशंकाओं को दूर करने के लिए, हम जमानत की शर्तें और कठोर कर सकते हैं।अपीलकर्ता द्वारा साक्षीयों को प्रभावित करने के संबंध में, यह स्पष्ट है कि ऐसी किसी भी स्थिति में, यह जमानत की रियायत का दुरुपयोग माना जाएगा और इसके लिए आवश्यक परिणाम भुगतने होंगे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. सर्वोच्च न्यायालय ने इसी समय की एक गिरफ्तारी को रद्द करते हुए कहा:

"जहां अन्वेषण एजेंसी को आरोपी की गिरफ्तारी से काफी पहले उसकी भूमिका की जानकारी थी... और फिर भी उसे तभी गिरफ्तार करने का विकल्प चुना गया जब वह जमानत हासिल करने के कगार पर था... ऐसा आचरण दुर्भावना का संकेत देता है और हस्तक्षेप का हकदार है।"यही सिद्धांत मोहम्मद जुबैर बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली), (2023) 16 एससीसी 764 (गिरफ्तारी अनियंत्रित नहीं) और सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2022) 1 एससीसी 676 (जघन्य अपराध के लिए अभिरक्षा/अभिरक्षा की आवश्यकता/साक्षी के खतरे के लिए ही अभिरक्षा) के प्रकरण में अधिक बलपूर्वक लागू होता है।"

II. गिरफ्तारी धारा 35(बी) बीएनएसएस के तहत वैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करती है – कोई पूर्व शर्त पूरी नहीं हुई है।

11. न तो गिरफ्तारी के आधार और न ही दिनांक 24.09.2025 के रिमांड आवेदन में कोई ऐसी सामग्री, और तो और कोई ठोस सामग्री भी, प्रकट नहीं होती है जो धारा 35(बी) बीएनएसएस के तहत वैधानिक अनिवार्यता को संतुष्ट करती है।

• आगे अपराध को रोकना:इस बात की कोई विशेष आशंका नहीं है कि आवेदक कोई और अपराध करेगा; उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और न ही उसे कोई आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त है।

• अन्वेषण में सहायता करना:उनकी गिरफ्तारी के समय तक, अन्वेषण पहले ही 21 महीने से चल रही थी; छह आरोपपत्र दायर किए जा चुके थे; और अन्वेषण एजेंसी ने स्वयं दर्ज किया है कि आवेदक से पूछताछ एक संक्षिप्त दो घंटे के सत्र में समाप्त हो गई थी।उनकी बाद की अभिरक्षा से कोई नई अन्वेषण प्रक्रिया प्रारम्भ होने का कोई प्रमाण नहीं है।

• छेड़छाड़ रोकना:यह प्रकरण पूरी तरह से दस्तावेजी है।संबंधित सभी सामग्री को ईडी/ईओडब्ल्यू द्वारा बहुत पहले ही जब्त कर लिया गया है, और आगे किसी भी प्रकार की बरामदगी लंबित नहीं है।

• उपस्थिति सुनिश्चित करना:आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी है, जिसकी यहाँ गहरी जड़ें हैं और उसने सदैव विधि का सहयोग किया है; इन परिस्थितियों में, अभिरक्षा अंतिम उपाय नहीं बल्कि पहली सहज प्रतिक्रिया थी। रिमांड आदेश में "उसकी निर्माण कंपनी को धन भेजने" का निराधार आरोप किसी भी आरोपपत्र या ईडी के अभिलेख में प्रमाणित नहीं होता है।इसलिए, यह गिरफ्तारी आकस्मिक है, आवश्यकतावश नहीं।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

IV. आगे की पूरी अन्वेषण प्रारंभ से ही अमान्य है – यह अनिवार्य न्यायालयी अनुमति के बिना की गई है, जिससे गिरफ्तारी अवैध हो जाती है।

12. यह प्रकरण एक व्यवस्थागत खामी को उजागर करता है:

आरोपपत्र दाखिल करने के बाद भी अनियंत्रित अन्वेषण।1 जुलाई 2024 को आरोप पत्र संख्या 03/2024 दाखिल करने के बाद (जिसमें स्पष्ट रूप से "आगे की अन्वेषण जारी है" लिखा था), ईओडब्ल्यू ने पांच पूरक आरोप पत्र दाखिल कीं जिनमें 47 अतिरिक्त आरोपियों को शामिल किया गया – ये सभी कार्यवाही धारा 173(8) बीएनएसएस के तहत न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना की गईं।संबंधित विशेष न्यायालय के समक्ष अनुमति मांगने के लिए कभी कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था।आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आवेदक को फंसाने को उचित ठहराने के लिए कोई नई सामग्री नहीं मिली (41वीं विधि आयोग रिपोर्ट, कंडिका 17.12)।सर्वोच्च न्यायालय ने आधिकारिक रूप से यह बात कही है:विनय त्यागी बनाम इरशाद अली, (2013) 5 एससीसी 762 में यह देखा गया है कि"अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने के बाद... पुलिस को न्यायालय से औपचारिक अनुमति लेनी चाहिए... टुकड़ों में अन्वेषण करना अस्वीकार्य है।"यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

"ग. विनय त्यागी के प्रकरण (ऊपर) में कंडिका 49 में निम्नलिखित कहा गया है:

"49.अब, हम एक और महत्वपूर्ण पहलू की जांच कर सकते हैं कि धारा 173(8) के प्रावधानों को न्यायालय और अन्वेषण एजेंसियों द्वारा कैसे समझा और लागू किया गया है।यह सत्य है कि यद्यपि संहिता की धारा

173(8) के प्रावधानों में न्यायालय की अनुमति से "आगे की अन्वेषण" करने या पूरक रिपोर्ट दाखिल करने की कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं है, अन्वेषण एजेंसियों ने न केवल इसे समझा है बल्कि इसे एक विधिक प्रथा के रूप में भी अपनाया है कि न्यायालयों से "आगे की अन्वेषण" करने और न्यायालय की अनुमति से "पूरक रिपोर्ट" दाखिल करने की अनुमति मांगी जाए।कुछ निर्णय में न्यायालय ने भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया है।"आगे की अन्वेषण" करने और/या "पूरक रिपोर्ट" दाखिल करने के लिए न्यायालय की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता को पढ़ा जाना चाहिए, और यह संहिता की धारा 173(8) के प्रावधानों का एक आवश्यक निहितार्थ है।समकालीन व्याख्या का सिद्धांत व्याख्या में पूरी तरह से सहायक होगा क्योंकि लंबे समय से समझे और लागू किए गए प्रकरण और विधि द्वारा समर्थित प्रथाओं को व्याख्यात्मक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।"

13. "विनुभाई हरिभाई मालवीय बनाम गुजरात राज्य" के प्रकरण में,(2019) 17 एससीसी 1 में यह देखा गया है कि:"

42. इन निर्णयों में न्यायालय द्वारा कोई अच्छा कारण नहीं दिया गया है कि किसी मजिस्ट्रेट की आगे की अन्वेषण का आदेश देने की शक्तियां प्रक्रिया जारी होने और आरोपी के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने पर अचानक क्यों समाप्त हो जाएंगी, जबकि साथ ही साथ, पुलिस की अपराध की आगे की अन्वेषण करने की शक्ति विचारण की शुरुआत तक जारी रहती है।ऐसा दृष्टिकोण इस न्यायालय के पूर्व के निर्णयों, विशेष रूप से साकिरी (उपरोक्त), समाज परिवर्तन समुदाय (उपरोक्त), विनय त्यागी (उपरोक्त) और हरदीप सिंह (उपरोक्त) के अनुरूप नहीं होगा; हरदीप सिंह (उपरोक्त) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपराधिक विचारण संज्ञान लेने के बाद प्रारम्भ नहीं होता, बल्कि आरोप निर्धारित होने के बाद ही प्रारम्भ होता है।इस न्यायालय के हाल के निर्णयों में जिस बात को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया है, वह है संविधान का अनुच्छेद 21 और यह तथ्य कि यह अनुच्छेद निष्पक्ष और न्यायपूर्ण अन्वेषण से कम कुछ भी नहीं मांगता है।यह कहना कि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण अन्वेषण से यह निष्कर्ष निकलेगा कि पुलिस के पास धारा 173(8) के तहत मजिस्ट्रेट की सहमति के अधीन, आरोप निर्धारित होने तक अपराध की आगे अन्वेषण करने की शक्ति बनी रहती है, लेकिन यह कहना कि मजिस्ट्रेट का पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार पूर्व–परीक्षण कार्यवाही के बीच में अचानक समाप्त हो जाता है, न्याय का घोर उपहास होगा, क्योंकि कुछ प्रकरण में आगे की अन्वेषण की आवश्यकता हो सकती है ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को त्रुटिपूर्ण तरीके से आरोपी न बनाया जाए या प्रथम दृष्टया दोषी व्यक्ति को इस तरह छूट न दी जाए। मजिस्ट्रेट की शक्तियों के ऐसे संकीर्ण और प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण का कोई औचित्य नहीं है, विशेष रूप से जब ऐसी शक्तियां सीआरपीसी की धारा 156(3) को धारा 156(1), धारा 2(एच) और धारा 173(8) के साथ पढ़ने से प्राप्त होती हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और विचारण प्रारम्भ होने से पहले आपराधिक प्रकरण की प्रगति के सभी चरणों में उपलब्ध होंगी।यह न्याय के हित में भी होगा कि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं स्वतः संज्ञान लेकर इस शक्ति का प्रयोग किया जाए।आगे की अन्वेषण का आदेश दिया जाना चाहिए या नहीं, यह विद्वान मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है, जो प्रत्येक प्रकरण के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तथ्यों के आधार पर और विधि के अनुसार ऐसे विवेक का प्रयोग करेंगे।उदाहरण के लिए, यदि ऐसे नए तथ्य सामने आते हैं जिनसे कुछ व्यक्तियों को दोषी ठहराया जा सकता है या उन्हें निर्दोष साबित किया जा सकता है, तो किसी आपराधिक प्रकरण में सच्चाई तक पहुंचना और पर्याप्त न्याय करना, आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने में होने वाली तथा विलंब से बचने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, जैसा कि हसनभाई वलीभाई कुरैशी (उपरोक्त) में कहा गया था।अतः, अमृतभाई शंभूभाई पटेल (उपरोक्त), अतुल राव (उपरोक्त) और बिकाश रंजन राउत (उपरोक्त) के निर्णयों में जहां तक इसके विपरीत निर्णय दिए गए हैं, वे निरस्त माने जाते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रणधीर सिंह राणा बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1997) 1 एससीसी 361 और रीता नाग बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (2009) 9 एससीसी 129 के निर्णय भी निरस्त माने जाते हैं।"

14. आगे की अन्वेषण के लिए न्यायिक स्वीकृति आवश्यक है... ताकि अनावश्यक खोजबीन को रोका जा सके। इसी प्रकार, "रॉबर्ट लालचुंगनुंगा चोंगथु बनाम बिहार राज्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 251" में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. इस प्रकरण को समाप्त करने से पहले, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझते हैं:

(i) विनय त्यागी बनाम इरशाद अली27 के मामले में यह देखा जा सकता है कि पूरक आरोपपत्र दाखिल करने के लिए न्यायालय की अनुमति लेना, धारा 173(8) सीआरपीसी का एक भाग है। ऐसी स्थिति में, हमारे विचार से, न्यायालय ऐसी अनुमति देकर अपने कार्य–अधिकार समाप्त नहीं कर देता है।चूंकि आगे की अन्वेषण न्यायालय की अनुमति से की जा रही है, इसलिए इसका न्यायिक प्रबंधन/नियंत्रण एक ऐसा कार्य है जिसे न्यायालय को ही निभाना चाहिए।

(ii) आपराधिक विधि की कार्यप्रणाली के सुचारू संचालन के लिए तर्क अपरिहार्य हैं।वे न्याय व्यवस्था में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही की आधारशिला हैं।यदि न्यायालय को यह ज्ञात होता है या आरोपी यह आरोप लगाता है (स्पष्ट रूप से आरोप को प्रमाणित करने के लिए सबूत और कारण के साथ) कि प्रथम सूचना रिपोर्ट और अंतिम आरोप पत्र के बीच बड़ा अंतर है, तो न्यायालय अन्वेषण एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगने और दिए गए स्पष्टीकरण की उपयुक्तता से स्वयं को संतुष्ट करने के लिए बाध्य है।उपरोक्त निर्देश केवल इसी प्रकरण के आधार पर नहीं दिया गया है।इस न्यायालय ने कई दुर्भाग्यपूर्ण अवसरों पर यह देखा है कि आरोपपत्र दाखिल करने/संज्ञान लेने आदि में भारी देरी होती है। इस न्यायालय ने अपने निर्णयों में बार–बार इस बात पर जोर दिया है कि त्वरित अन्वेषण तथा विचारण आरोपी, पीड़ित और समाज के लिए महत्वपूर्ण है।हालांकि, कई कारणों से इस मान्यता को वास्तविकता में बदलने में अभी भी देरी हो रही है।

(iii) जबकि यह सर्वविदित और मान्यता प्राप्त है कि अन्वेषण प्रक्रिया में कई गतिशील पहलू होते हैं और इसलिए सख्त समयसीमा निर्धारित करना अव्यावहारिक है, वहीं साथ ही, इस निर्णय के पूर्व भाग में की गई चर्चा स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि अन्वेषण अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकती है।अभियुक्त को यह

उम्मीद करने का पूरा अधिकार है कि एक निश्चित समय के बाद उसके खिलाफ लगे आरोपों के बारे में निश्चितता प्राप्त हो जाए, जिससे उसे अपना बचाव तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।यदि किसी विशेष अपराध का अन्वेषण अनुचित रूप से लंबी अवधि तक जारी रही है, वह भी पर्याप्त औचित्य के बिना, जैसा कि इस प्रकरण में है, तो आरोपी या परिवादी दोनों को धारा 528 बीएनएसएस/482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय में जाकर अन्वेषण की अद्यतन जानकारी प्राप्त करने या, यदि आरोपी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, तो प्रकरण को रद्द करने की अनुमति होगी।यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्वेषण पूरी होने में देरी केवल एक आधार के रूप में कार्य करेगी, और यदि न्यायालय अपने विवेक से इस आवेदन पर विचार करने का निर्णय लेता है, तो अन्य आधारों पर भी विचार करना होगा।

(iv) कारण न केवल न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि प्रशासनिक प्रकरण में भी उतने ही आवश्यक हैं, विशेष रूप से प्रतिबंध जैसे प्रकरण में, क्योंकि वे अधिक गंभीर परिणामों का मार्ग प्रशस्त करते हैं।स्वीकृति देने या अस्वीकार करने वाले अधिकारियों द्वारा निर्णय लेने में विवेक का प्रयोग स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, जिसमें निष्कर्ष पर पहुंचने के दौरान उनके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करना भी शामिल है।"

15. अब सभी आरोपपत्र दाखिल होने के बाद की अन्वेषण के लिए न्यायालय की अनुमति अनिवार्य है। इसी पीठ ने चैतन्य बघेल बनाम ईडी (सीआर.एम.पी.संख्या 2506/2025 दिनांक 17.10.2025, कंडिका 86, 103) में अभिनिर्धारित कियाः:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"86. अतः, अन्वेषण एजेंसी का यह कर्तव्य है कि एक बार मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दर्ज होने और मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के बाद आगे का अन्वेषण मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही की जानी चाहिए।हरदीप सिंह (उपरोक्त) के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विचारण तभी प्रारम्भ होता है जब आरोप निर्धारित किए जाते हैं।हालांकि, यदि उत्तरवादी ने सक्षम न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना जांच की है, तो यह परिवाद प्रकरण और निर्णय प्राधिकारी के समक्ष अन्वेषण को नियंत्रित करने वाले प्रक्रियात्मक ढांचे का सख्ती से पालन नहीं कर सकती है।अवैधता का अर्थ है विधि का मौलिक उल्लंघन जिसे सुधारा नहीं जा सकता है, जबकि अनियमितता प्रक्रियात्मक विचलन है जिसे अक्सर सुधारा या नियमित किया जा सकता है।इसके बावजूद, ऐसा विचलन, भले ही अनियमित हो, कार्यवाही को अमान्य नहीं करेगा या अवैधता की श्रेणी में नहीं आएगा।

XXXXXXXX XXXX

103.याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका में उठाए गए आधार प्रक्रियात्मक चूक/अनियमितताएं हैं, जो अवैधता की श्रेणी में नहीं आतीं है।उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने लिखित निवेदन के कंडिका 70 में कहा है कि याचिकाकर्ता को नियमित जमानत के उपाय का सहारा लिया जाना चाहिए, जिसके तहत अभिरक्षा से रिहाई के लिए याचिकाकर्ता को पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत की अनिवार्य दोहरी शर्तों को पूरा करना होगा।मैं उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए इस तर्क से सहमत हूं कि इस याचिका में उठाए गए

आधार प्रक्रियात्मक चूक/अनियमितताएं हैं जो अवैधता की श्रेणी में नहीं आतीं और ये जमानत के आधार हैं। पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, इस न्यायालय को अन्वेषण एजेंसी द्वारा की गई अन्वेषण या गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है।अतः याचिका खारिज की जाती है।"न्यायालय की अनुमति के अभाव में आगे की अन्वेषण प्रारम्भ से ही अमान्य हो जाती है – जो जमानत के लिए एक ठोस आधार है।"इस प्रकार की अवैध कार्यवाही के दौरान गिरफ्तारी मान्य नहीं हो सकती है।"

V. समता के आधार पर रिहाई कि मांग– ऐसे अन्वेषण प्रक्रिया जिसे अत्यधिक पक्षपातपूर्ण, चयनात्मक और मनमाना गया है

16. समानता के आधार पर आवेदक की रिहाई के लिए ठोस तर्क:समता का सिद्धांत केवल न्यायसंगत ही नहीं है; यह अनुच्छेद 14 के तहत एक संवैधानिक अनिवार्यता है – समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।51 आरोपियों से जुड़े इस विशाल शराब गिरोह में, ईओडब्ल्यू की चुनिंदा गिरफ्तारियां और रिहाई एक खतरनाक मनमानी कार्यप्रणाली को उजागर करती हैं जो न्यायिक विवेक को झकझोर देती है।जबकि आवेदक निराधार अफवाहों के आधार पर हिरासत में है, वहीं सरगना और प्रमुख लाभार्थी स्वतंत्र घूम रहे हैं। इस अभियोजन में समानता का वह अचूक सिद्धांत व्याप्त है जो अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक आदेश की तरह लागू होता है।निम्नलिखित सह–आरोपियों पर विचार करते हुए, जिन सभी की भूमिकाएँ अधिक गंभीर हैं, फिर भी उन्हें लगातार उच्च न्यायालयों द्वारा जमानत दी गई है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अरुण पति त्रिपाठी, जिन्हें ए–1 के रूप में नामित किया गया था और जिन पर राजनेताओं और अधिकारियों को धन वितरण सहित पूरे शराब घोटाले के संचालन को अंजाम देने का कथित मास्टरमाइंड/मुख्य षड्यंत्रकर्ता होने का आरोप था, को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 1263/2025 दिनांक 07.03.2025 में जमानत प्रदान की; त्रिलोक सिंह ढिल्लों, जिसे ए–5 के रूप में नामित किया गया था और जिसे लाइसेंस प्राप्त दुकानों के माध्यम से नकदी लेनदेन और कमीशन वितरण के साथ अवैध शराब आपूर्ति श्रृंखला को संचालित करने वाले प्रमुख सिंडिकेट लाभार्थी के रूप में पहचाना गया था, ने एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 14697/2024 दिनांक 27.11.2024 में सर्वोच्च न्यायालय से स्वतंत्रता प्राप्त की; अनुराग द्विवेदी, जो ए–5 के रूप में भी नामित थे और सिंडिकेट नेटवर्क में करोड़ों रुपये की आबकारी अपराध की रकम एकत्र करने और वितरित करने वाले कैश एग्रीगेटर के रूप में कार्यरत थे, को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 18386/2024 दिनांक 07.03.2025 के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया;अरविंद सिंह, जो आबकारी विभाग से सीधे संबंध रखने और गिरोह के लिए अवैध शराब लाइसेंस और कोटा की सुविधा प्रदान करने वाले ए–2 के रूप में नामित थे, ने दाण्डिक अपील संख्या 2699/2025 दिनांक 19.05.2025 में सर्वोच्च न्यायालय से राहत प्राप्त की;संजय कुमार मिश्रा, जिसे ए–4 के रूप में नामित किया गया था और जो शराब बनाने वालों और राजनीतिक लाभार्थियों के बीच समन्वय स्थापित करने वाले प्रमुख सह–षड्यंत्रकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था, को इसी न्यायालय द्वारा एम.सीआर.सी. संख्या 7093/2025 दिनांक 23.09.2025 में जमानत दी गई थी;विजय भाटिया, जिसे ए–41 के रूप में नामित किया गया है और बेनामी

संपत्तियों में निवेश किए गए पर्याप्त अवैध कमीशन प्राप्त करने वाले प्रमुख लाभार्थी के रूप में पहचाना गया है, ने एम.सीआर.सी. संख्या 5601/2025 दिनांक 25.09.2025 में इस न्यायालय से जमानत प्राप्त की;तथा सुनील दत्त, जो ए–10 के रूप में नामित थे और नकली शराब के परिवहन और वितरण के लिए रसद संभालने वाले सिंडिकेट सदस्य के रूप में परिचालन भूमिका निभा रहे थे, को इस न्यायालय द्वारा एम.सीआर.सी. संख्या 188/2025 दिनांक 12.03.2025 में रिहा कर दिया गया था।ये उदाहरण अपवाद नहीं बल्कि नियम हैं:छह आरोपपत्रों में नामित 51 आरोपियों में से 29 को बिना किसी गिरफ्तारी के ही आरोपपत्र में शामिल किया गया है, जबकि गिरफ्तार किए गए 22 लोगों में से 12 (55% से अधिक) को सर्वोच्च न्यायालय और स्वयं इस न्यायालय द्वारा जमानत दी जा चुकी है, जिनमें मुख्य सरगना, नकदी संग्राहक, उत्पाद शुल्क अधिकारी और प्रत्यक्ष लाभार्थी शामिल हैं – इन सभी की भूमिकाएं आवेदक के खिलाफ लगाए गए मामूली "धन हेरफेर" के आरोप से कहीं अधिक गंभीर हैं, जिसका नाम एफआईआर और हर आरोपपत्र में नहीं हैयह चुनिंदा कार्यप्रणाली, जिसमें भगोड़ा लक्ष्मीनारायण बंसल (जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार प्रकरण संख्या 01/2024 में दिनांक 19.05.2025 का अनिश्चितकालीन गिरफ्तारी वारंट अभी भी प्रभावी है) स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, जबकि केवल उसके दूषित बयान के आधार पर आवेदक की अभिरक्षा बरकरार है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए स्पष्ट भेदभाव का गठन करती है।जैसा कि विपिन यादव बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2025 एससीसी ऑनलाइन डेल 6237 (पैरा 31, 39–40) में कहा गया है, जहां समान या अधिक गंभीर आरोपों वाले सह–आरोपी को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, वहां समानता अपरिहार्य हो जाती है; इसका इनकार न्यायिक विवेक को झकझोरता है और आवेदक की तत्काल रिहाई अनिवार्य बनाता है।यह अभिनिर्धारित किया गया है किः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. आवेदकों ने मूल रूप से अपनी जमानत याचिका इस आधार पर दायर की है किउत्तरवादी विभाग ने आरोपी अग्रवाल को गिरफ्तार न करके चुनिंदा रणनीति अपनाई है, जो कथित तौर पर स षड़यंत्र का असली मास्टरमाइंड है और उस पर धन के स्रोत के बारे में जानकारी होने और फर्जी खातों की व्यवस्था करने का भी आरोप है।यह तर्क दिया गया है कि आरोपी कथित षड़यंत्र के सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, हालांकि उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।यह तर्क दिया गया है कि आरोपी रोहित को परिवाद मे षड़यंत्र का मास्टरमाइंड बताया गया है और उसकी भूमिका याचिकाकर्ताओं के समान, या उनसे भी अधिक गंभीर है।

39. हाल ही में, हिमांश उर्फ हिमांशु बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 4697 के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी को इस आधार पर जमानत पर रिहा कर दिया था कि कथित अपराध के मुख्य षड़यंत्रकर्ता को कभी भी प्रकरण में पेश नहीं किया गया था।समान परिस्थितियों वाले सह–आरोपियों की गिरफ्तारी न होना, समतुल्य पीठ न्यायालयों द्वारा आरोपी को जमानत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है [संदर्भ: बिंद बनाम गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय]जमानत आवेदन. 3642 रमेश मंगलानी बनाम ईडी, (2023) 7 एचसीसी (डेल) 134; संजय का प्रवर्तन निदेशालय, 2024 एससीसी ऑनलाइन डेल 9569; आदि।]।पूर्व उदाहरणों से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि अन्वेषण एजेंसी द्वारा चयनात्मक

अभियोजन की सुसंगतता, जो स्पष्ट रूप से मनमानी है, जमानत देने के प्रश्न पर विचार करते समय नजरअंदाज की जा सकती है।

40. उत्तरवादी विभाग द्वारा ऐसे आरोपी को गिरफ्तार न किए जाने के कारण, जिसकी भूमिका आवेदकों से अधिक प्रतीत होती है, और यहां तक कि उस व्यक्ति को भी न्यायालय में पेश न किए जाने के कारण, जिसने अवैध खातों की व्यवस्था करने में सहायता की थी, प्रथम दृष्टया उत्तरवादी विभाग का दृष्टिकोण मनमाना प्रतीत होता है और आवेदकों को समानता का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता है।"चयनात्मक अभियोजन का सांख्यिकीय आरोपःकुल नामित अभियुक्तः51 गिरफ्तारी के बिना आरोप पत्रः

29.गिरफ्तार किये गये :22.

पहले से ही प्रदान किया गया जमानत :12.

अभिरक्षा मे रखे गये :––यह आँकड़ा बहुत कुछ बताता हैःआरोपपत्र दाखिल होने के बावजूद आधे आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं; गिरफ्तार किए गए लोगों में से अधिकांश को रिहाई मिल गई है।एफआईआर/छह आरोपपत्रों में आवेदक का नाम नहीं है, कोई बरामदगी नहीं की गई है, हालांकि उसके साथ भेदभाव किया गया है।सबसे जघन्य उल्लंघनःरायपुर की विशेष न्यायालय (पीसी अधिनियम) द्वारा 19.05.2025 को जारी अनिश्चितकालीन गिरफ्तारी वारंट (भ्रष्टाचार प्रकरणसंख्या 01/2024) के तहत लक्ष्मी नारायण बंसल (पप्पू बंसल) के खिलाफ जारी वारंट को कभी रद्द/वापस नहीं लिया गया।मुख्य नकद संवाहक के रूप में उनकी भूमिका; उनका विधिक रूप से अमान्य बयान (वारंट सक्रिय रहते हुए दर्ज किया गया, जो धारा 72 बीएनएसएस का उल्लंघन है) आवेदक की गिरफ्तारी का एकमात्र आधार है।विडंबना यह है कि ईओडब्ल्यू न तो उन्हें गिरफ्तार करता है और न ही वारंट रद्द करता है, फिर भी आवेदक की जमानत का विरोध करने के लिए उनके बयान पर निर्भर करता है।जैसा कि विपिन यादव बनाम प्रवर्तन निदेशालय (उपरोक्त) प्रकरण में कहा गया है, "जहां समान या अधिक गंभीर आरोपों वाले सह–आरोपियों को जमानत दी गई है, वहां समानता अपरिहार्य हो जाती है।जमानत संबंधी न्यायशास्त्र में भेदभाव अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।"

17. इसी प्रकार, **कृष्णन सुब्रमणियन बनाम राज्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 1384** के प्रकरण में, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है :

"17. विद्वान एएससी ने प्रस्तुत किया कि प्रकरण की संवेदनशील प्रकृति और इसमें शामिल बड़ी रकम को देखते हुए, आवेदक के फरार होने तथा विचारण का सामना न करने की प्रबल संभावना है।इसके अलावा, यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह साक्षीयों को प्रभावित कर सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है क्योंकि समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में, उसके रेलिगेयर समूह के कर्मचारियों के साथ व्यापक संबंध और रुतबा था।यह दृढ़तापूर्वक निवेदन किया जाता है कि आवेदक इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की अनुतोष पाने का हकदार नहीं है और यह आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

XXXX XXXX XXXX

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. वर्तमान प्रकरण में यह स्वीकार किया गया है कि सह–आरोपी मनिंदर सिंह को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 5 मई 2021 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया गया था।उक्त जमानत आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी (सीआरएल) डायरी संख्या 12290/2021 के माध्यम से चुनौती दी गई थी।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 12 जुलाई 2021 के आदेश द्वारा 5 मई 2021 के जमानत आदेश की पुष्टि की और एसएलपी को खारिज कर दिया। सह–आरोपी अनिल सक्सेना को भी इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 17 जून 2020 के आदेश द्वारा जमानत आवेदन संख्या 1074/2020 में जमानत पर रिहा कर दिया था।उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी (सीआरएल) डायरी संख्या 13106/2020 के माध्यम से चुनौती दी गई थी।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 17 जुलाई 2020 के आदेश द्वारा सह–आरोपी अनिल सक्सेना की जमानत याचिका में कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

24. अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, अन्वेषण अधिकारियों द्वारा सभी सामग्री एकत्र कर ली गई है और आवेदक के विरुद्ध साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं।इस न्यायालय की राय में, आवेदक न तो भागने का जोखिम रखता है और न ही उसके द्वारा किसी भी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने या किसी साक्षी को प्रभावित करने की कोई प्रवृत्ति हो सकती है, क्योंकि साक्ष्य का संपूर्ण क्षेत्र दस्तावेजी प्रकृति का है, जो वर्ष 2008 से बिना किसी बाधा या छेड़छाड़ के यथावत मौजूद है।आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड बेदाग है।वह 8 दिसंबर 2021 से जेल में बंद है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, आरोपपत्र, प्रथम पूरक आरोपपत्र और द्वितीय पूरक आरोपपत्र पर विचार करते हुए, साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अन्य सह–आरोपियों को समन्वय पीठ द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कर दी है; और उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों और चर्चा के आधार पर, यह न्यायालय नियमित जमानत की इस याचिका को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. यद्यपि अपराधों की गंभीरता गंभीर है, फिर भी यह समानता के सिद्धांत को नकार नहीं सकती है। अभियोजन पक्ष के स्वयं के तर्कों के आधार पर भी, आवेदक की स्थिति उन कई सह–आरोपियों की तुलना में काफी बेहतर और अधिक अनुकूल है जिन्हें पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।अन्य आरोपियों के विपरीत, अभियुक्त ए–1 का नाम एफआईआर या किसी भी आरोपपत्र में नहीं है; ईओडब्ल्यू द्वारा उसके विरुद्ध कभी कोई समन, नोटिस या पूर्व तलाशी नहीं ली गई, हालांकि अन्य सह–आरोपियों से बार–बार पूछताछ की गई और उनके परिसरों पर छापे मारे गए।स्वीकार किए गए नकदी संग्राहकों और फील्ड ऑपरेटरों से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है, इसके विपरीत अभियुक्त से कोई नकदी, दस्तावेज या अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद नहीं हुई हैं।यहां तक कि अभियोजन पक्ष के विवरण के अनुसार भी, आवेदक के खिलाफ आरोप "धन के लेन–देन" की एक सहायक या मामूली भूमिका तक ही सीमित है, जबकि जमानत प्राप्त करने वाले सह–आरोपियों को सिंडिकेट में निर्माण, आपूर्ति, भंडारण, परिवहन, नकदी संग्रह और वितरण में मुख्य परिचालन भूमिकाएं सौंपी गई हैं।आवेदक पहली बार अपराध करने वाला व्यक्ति है जिसका कोई पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि

नहीं है, जबकि कई सह–आरोपी कई वर्षों से शराब सिंडिकेट में बार–बार शामिल होने के आरोपी हैं।यदि अरुण पति त्रिपाठी (ए–1), जिसे मुख्य षड़यंत्रकर्ता बताया गया है, को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतंत्रता का पात्र पाया गया है, और यदि त्रिलोक सिंह ढिल्लों जैसे व्यक्तियों को, जिनके कथित धन साम्राज्य कहीं अधिक मजबूत हैं, सशर्त रिहाई दी गई है, तो न्यायसंगतता और कानून के अनुसार, यह माननीय न्यायालय आवेदक को समान राहत देने से इनकार नहीं कर सकता, जिसकी भूमिका स्पष्ट रूप से कम है।

V. क्लासिक ट्रिपल टेस्ट पूरी तरह से संतुष्ट है – भागने का कोई खतरा नहीं, छेड़छाड़ की कोई आशंका नहीं, पूर्ण सहयोग सुनिश्चित।

19. आवेदक के भागने का जोखिम सिद्ध नहीं होता है।वह छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी है, जिसका परिवार, संपत्ति और व्यावसायिक हित राज्य के भीतर मजबूती से स्थापित हैं, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और उसने कभी भी किसी भी स्तर पर कानून की किसी भी प्रक्रिया से बचने या उसमें बाधा डालने का प्रयास नहीं किया है।

20. साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की भी कोई वास्तविक संभावना नहीं है।अभियोजन पक्ष का प्रकरण पूरी तरह से दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है; अन्वेषण एजेंसियों ने पहले ही लगभग 885 साक्षीयों का उल्लेख किया है और लगभग 939 दस्तावेज़ जब्त किए हैं जो हजारों पृष्ठों के हैं, और आगे किसी भी प्रकार की खोज या बरामदगी लंबित नहीं है।जमानत का उद्देश्य उपस्थिति सुनिश्चित करना है, न कि दंड देना।सर्वोच्च न्यायालय ने **संजय चंद्र बनाम सीबीआई (2012) 1 एससीसी 40** प्रकरण में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"23. जमानत से इनकार करने का उद्देश्य रोकथाम होना है, इस प्रश्न के अलावा, इस तथ्य को भी नहीं भूलना चाहिए कि दोषसिद्धि से पहले किसी भी कारावास में पर्याप्त दंडात्मक तत्व होता है और किसी भी न्यायालय के लिए यह अनुचित होगा कि वह पूर्व आचरण की अस्वीकृति के प्रतीक के रूप में जमानत से इनकार करे, चाहे आरोपी को इसके लिए दोषी ठहराया गया हो या नहीं, या किसी गैर–दोषी व्यक्ति को सबक सिखाने के उद्देश्य से उसे कारावास का अनुभव कराने के लिए जमानत से इनकार करे।

24. जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, वर्तमान प्रकरण में अपीलकर्ताओं के विरुद्ध "आरोप का मुख्य बिंदु" "आरोप की गंभीरता" है।आरोपित अपराध आर्थिक अपराध हैं, जिनके कारण राज्य के खजाने को नुकसान हुआ है।हालांकि, उनका तर्क है कि अपीलकर्ताओं द्वारा साक्षीयों को प्रभावित करने की संभावना है, लेकिन उन्होंने इस आरोप के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया है।हमारी राय में, जमानत आवेदनों पर विचार करते समय आरोप की गंभीरता निस्संदेह एक महत्वपूर्ण पहलू है, परंतु यह एकमात्र मापदंड या कारक नहीं है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, वह है भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विचारण तथा दोषसिद्धि के बाद दी जाने वाला दंड। अन्यथा, यदि केवल दंड संहिता को ही आधार बनाया जाए, तो हम संवैधानिक अधिकारों का संतुलन नहीं साध रहे होंगे, बल्कि न्याय के तराजू को ही उलट रहे होंगे।

XXXXXXXXXXXXXX

42. जब विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित काल के लिए जेल अभिरक्षा में रखा जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है।अभिरक्षा में लिए गए या गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को शीघ्र सुनवाई का अधिकार है; प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान प्रकरण में यह संभव है?

43. सत्रह अभियुक्त व्यक्ति हैं।साक्षीयों के बयान कई सौ पृष्ठों के हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, वे भी विपुल हैं।विचारण की सुनवाई में काफी समय लग सकता है और हमें लगता है कि अपीलकर्ताओं को, जो जेल में हैं, दोषी पाए जाने की स्थिति में हिरासत की अवधि से भी अधिक समय तक जेल में रहना पड़ेगा।यह न्याय के हित में यह उचित नहीं है कि आरोपी अनिश्चित काल तक जेल में रहे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाया गया आरोप राज्य के खजाने को हुए भारी नुकसान के संदर्भ में एक गंभीर अपराध है, लेकिन यह बात हमें अपीलकर्ताओं को जमानत पर रिहा करने से नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि उत्तरवादी की ओर से ऐसा कोई ठोस तर्क नहीं है कि यदि आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे विचारण में हस्तक्षेप करेंगे या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेंगे।अन्वेषण पूरी होने और आरोपपत्र दाखिल होने के बाद भी आरोपी को अभिरक्षा में रखने का हमें कोई अच्छा कारण नजर नहीं आता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

VI. प्रथम दृष्टया कोई प्रकरण बनता ही नहीं – रेत पर बना महल:

21. सम्मानपूर्वक कहें तो, गहन जांच–पड़ताल करने पर अभियोजन पक्ष का ढांचा ध्वस्त हो जाता है।यह लगभग पूरी तरह से पुराने, अप्रमाणित और विधिक रूप से कमजोर धारा 161 बीएनएसएस के बयानों पर आधारित है, जिनका कोई ठोस स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, और प्रथम दृष्टया भी यह आरोपित अपराधों के आवश्यक तत्वों को उजागर करने में विफल रहता है।(i) धारा 161 के कथनों पर एकमात्र निर्भरता।

22. आवेदक के विरुद्ध प्रकरण मुख्य रूप से इस पर आधारित है:प्रोबीर शर्मा का दिनांक 04.12.2025 का बयान – एक सह–अपराधी का बयान – एफआईआर दर्ज होने के लगभग डेढ़ वर्ष पश्चात् दर्ज किया गया, जिसे यदि अक्षरशः यह सत्य भी मान लिया जाए, तो भी ईमेल, बहीखाता प्रविष्टियाँ, बैंकिंग निर्देश या डिजिटल साक्ष्य जैसे किसी भी स्वतंत्र समकालीन सामग्री द्वारा समर्थित नहीं है जो आवेदक को कथित धन के लेन–देन से जोड़ता है।लक्ष्मी नारायण बंसल का बयान – एक घोषित भगोड़ा जिसके खिलाफ एक सक्रिय गैर–जमानती गिरफ्तारी वारंट अभी भी लागू है, धारा 72 बीएनएसएस में निहित सुरक्षा उपायों के संदर्भ में उसके बयान को स्वाभाविक रूप से संदिग्ध और दूषित बनाता है, क्योंकि वह व्यक्ति जानबूझकर स्वयं को विधिक प्रक्रिया की पहुंच से बाहर रखता है।विधि में, किसी सह–अपराधी और भगोड़े द्वारा दिए गए ऐसे विलंबित और स्वार्थपरक बयान, जो अकेले और महत्वपूर्ण तथ्यों में विश्वसनीय पुष्टि के बिना हों, पूर्व–विचारण चरण में किसी नागरिक की स्वतंत्रता छीनने का ठोस आधार नहीं बन सकते है।(ii) अभियोजन पक्ष द्वारा सबूत पेश करने पर भी बुनियादी अपराध तत्वों का अभाव: जमानत के सीमित उद्देश्य के लिए अभियोजन पक्ष के विवरण को सही

मानते हुए भी, आरोपित कृत्य लागू धाराओं के मूल तत्वों को पूरा नहीं करते हैं।भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमःआवेदक स्पष्ट रूप से लोक सेवक नहीं है, और न ही किसी नामित लोक सेवक द्वारा रिश्वतखोरी या आपराधिक दुराचार के किसी विशिष्ट कृत्य में जानबूझकर सहायता करने का कोई ठोस प्रमाण है। पद पर आसीन व्यक्तियों से "लाभ" या "निकटता" के मात्र आरोप, बिना किसी परिभाषित कृत्य के, धारा 7 या 12 को संतुष्ट नहीं करते हैं।आईपीसी की धारा 467, 468, 471 (जाली दस्तावेज बनाना और जाली दस्तावेजों का उपयोग):आवेदक द्वारा किसी भी जाली दस्तावेज को बनाने, निष्पादित करने, गढ़ने, बदलने या उपयोग करने का आरोप नहीं है।कोई भी हस्तलेख, डिजिटल हस्ताक्षर, दस्तावेज ज़ब्ती या फोरेंसिक सामग्री उसे किसी भी होलोग्राम, निविदा पत्र, लाइसेंस या फर्जी अभिलेख से नहीं जोड़ती है।आई. पी. सी. की धारा 420 (छल):आवेदक द्वारा बेईमानी से संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करने या किसी विशेष व्यक्ति द्वारा उसके नुकसान के लिए कोई कार्य/चूक करने का कोई आरोप नहीं है, और न ही इसका कोई प्रमाण है। धोखाधड़ी और परिणामस्वरूप संपत्ति सौंपने के आवश्यक तत्व स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं।आई. पी. सी. की धारा 120–बी (आपराधिक षड़यंत्र):इस सामान्य दावे के अलावा कि आवेदक को कथित घोटाले से "लाभ" हुआ, ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है **जो आवेदक और नामित सह–आरोपी के बीच विचारों की समानता या किसी करार की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति को दर्शाता है,** जैसा कि राम शरण चतुर्वेदी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2022) 16 एससीसी 166 में कहा गया है, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मात्र संबंध या निकटता अपर्याप्त है, और साझा योजना को प्रत्यक्ष कृत्यों में रूपांतरित करने के ठोस सबूत होने चाहिए।((iii) जमानत अधिकारिता का दायरा–कोई लघु–विचारण नहीं।यह सर्वविदित है कि जमानत के चरण में न्यायालय को अंतिम निर्णय की तरह लघु परीक्षण करने या साक्ष्यों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं होती है; केवल प्रथम दृष्ट्या यह संतुष्टि आवश्यक है कि आरोप विश्वसनीय सामग्री द्वारा समर्थित है।जब, जैसा कि यहां है, प्रकरण अत्यधिक रुचि रखने वाले गवाहों के अप्रमाणित, विलंबित बयानों पर आधारित है और जब कथित अपराधों के वैधानिक तत्व स्वयं गंभीर संदेह में हैं, तो पहली बार आरोपी को विचारण से पहले निरंतर कारावास में रखना जमानत के स्थापित सिद्धांतों और अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. इन परिस्थितियों में, बुनियादी आपराधिक न्यायशास्त्र और प्रचलित मिसालों के आधार पर आवेदक के विरुद्ध अभियोजन प्रकरण इतना कमजोर प्रतीत होता है कि यह स्वतंत्रता से और अधिक वंचित करने को उचित नहीं ठहरा सकता है।

VII. अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन– लंबी अवधि की अभिरक्षा जहां विचारण एक दूर का मृगतृष्णा है:

24. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि वर्तमान कारावास प्रभावी रूप से सबूत के बजाय प्रक्रिया द्वारा दंड में परिवर्तित हो गया है।अभियोजन पक्ष का दावा है कि इसमें 51 आरोपी व्यक्ति, लगभग 1110 साक्षीयों और लगभग 990 दस्तावेज हैं जो हजारों पन्नों के हैं, जबकि अभी तक आरोप निर्धारित नहीं किए गए हैं और कई अन्य आरोपियों के संबंध में अन्वेषण जारी है।इन परिस्थितियों में,विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई

वास्तविक संभावना नहीं है, और आवेदक की निरंतर अभिरक्षा विचारण से पहले के दंड के समान होगी।कपिल वाधवान बनाम सीबीआई, 2025 आईएनएससी 1440, विशेष रूप से कंडिका 11–25 पर भरोसा किया गया है,जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी है कि एक बार अन्वेषण पूरी हो जाने और अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी सामग्री जुटा लेने के बाद, लंबी पूर्व–विचारण अभिरक्षा किसी भी वैध अन्वेषण उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है और अस्वीकार्य रूप से एक ठोस दंड का चरित्र धारण कर लेती है।इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है किः

11. दोनों पक्षों की बात विस्तार से सुनने के बाद, हमें जमानत संबंधी न्यायशास्त्र के कुछ स्थापित सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है।इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारतीय विधि के अंतर्गत "जमानत नियम है और कारावास अपवाद है" का सिद्धांत आपराधिक न्यायशास्त्र की मूल भावना में निहित है।यह नियम इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि आपराधिक विधि किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष मानता है जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाए।इसका अर्थ यह है कि सामान्यतः विचाराधीन कैदी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जाना चाहिए, जब तक कि समाज को स्पष्ट खतरा न हो, साक्षीयो/जांच को प्रभावित करने का जोखिम न हो या उसके भागने का खतरा न हो। यह नियम यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया को भी दंड न बनाया जाए, जिसके तहत किसी व्यक्ति को मुकदमे की प्रतीक्षा में कई वर्षों तक जेल में रखा जाता है। संहिता के तहत जमानत, दोषसिद्धि से पहले आरोपी का एक सीमित अधिकार है, जिसमें आरोपी को जमानत की गारंटी नहीं दी जाती, बल्कि अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का दायित्व होता है कि विचाराधीन कैदी को जमानत पर रिहा क्यों नहीं किया जाना चाहिए।उपरोक्त प्रस्ताव में कोई भी विचलन संवैधानिक दृष्टि से संदिग्ध है।

XXXXXXXXXXXXXXXXX

14.मूल रूप से, इस माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत की मांग करने वाला प्रत्येक आरोपी विचाराधीन कैदी होता है, जिसे निर्दोषता की धारणा का आवरण प्राप्त होता है, एक मूलभूत सिद्धांत जो केवल इसलिए भंग नहीं होता क्योंकि आरोप गंभीर हैं या लागू किया गया कानून कठोर है।अनेक निर्णयों के माध्यम से यह स्थापित हो चुका है कि विचारण से पहले की कैद को बिना न्यायनिर्णय के दंड में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और जहां लंबी अभिरक्षा असंगत, मनमानी या अत्यधिक हो जाती है, वहां न्यायालय का संवैधानिक दायित्व है कि वे हस्तक्षेप करें।हाल ही में इस न्यायालय ने जावेद गुलाम नबी शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2024) 9 एससीसी 813 6 के मामले में,गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत अभियोजित एक आरोपी को जमानत देते हुए, उसकी 4 साल की कैद और विचारण की उस अवस्था को ध्यान में रखा, जहां अभी आरोप निर्धारित नहीं हुए थे और अभियोजन पक्ष कम से कम अस्सी साक्षीयों से परीक्षा करने का आशय रखता था, और यह टिप्पणी की कि:

7. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, हमें आश्चर्य है कि अंततः यह विचारण कितने समय में समाप्त होगा। अपराध चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, भारत के संविधान के अनुसार आरोपी को शीघ्र विचारण का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिकार है।समय बीतने के साथ–साथ, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने विधि के एक बहुत ही सुस्थापित सिद्धांत को भुला दिया है कि जमानत को दंड के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए।

XXXXXX

17. यदि राज्य या संबंधित न्यायालय सहित किसी भी अभियोजन एजेंसी के पास संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी आरोपी के शीघ्र सुनवाई के मौलिक अधिकार को प्रदान करने या उसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, तो राज्य या कोई अन्य अभियोजन एजेंसी इस आधार पर जमानत याचिका का विरोध नहीं करेगी कि किया गया अपराध गंभीर है।संविधान का अनुच्छेद 21 अपराध की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना लागू होता है।

18. हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि याचिकाकर्ता अभी भी आरोपी है, दोषी नहीं।आपराधिक न्यायशास्त्र का सर्वोपरि सिद्धांत कि किसी आरोपी को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, चाहे दंड कानून कितना भी कठोर क्यों न हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. हम इस बात से आश्वस्त हैं कि जिस तरह से अभियोजन एजेंसी और न्यायालय ने कार्यवाही की है, उससे अभियुक्त के शीघ्र सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ है।(ज़ोर दिया गया) अतः,इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्णय पारित किया गया कि यदि राज्य के पास शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, तो वह अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत का विरोध नहीं कर सकता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुच्छेद 21 अपराध की प्रकृति की परवाह किए बिना लागू होता है।

15. उपरोक्त के अतिरिक्त, इस न्यायालय के समक्ष कई ऐसे मामले आए हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि बड़े पैमाने पर आर्थिक अपराधों के मामलों में जमानत देने के संबंध में अलग व्यवहार किया जाता है।इन मामलों में न्यायालय ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि बड़े पैमाने पर आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में जमानत देते समय कड़े से कड़े मानदंड लागू किए जाने चाहिए।[बिहार राज्य और अन्य बनाम अमित कुमार उर्फ बच्चा राय, (2017) 13 एससीसी 751।]

XXXXXXXXXXXXXXX

24. मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता पर 17 बैंकों के संघ से लिए गए ऋण और क्रेडिट सुविधा का भुगतान न करने और 81 शेल कंपनियों में धन का विनिवेश करने के कारण आरोप लगाया गया था।यह स्वीकार किया जाता है कि यह प्रकरण दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है और इन कंपनियों से जुड़े सभी आरोपियों को, अपीलकर्ताओं को छोड़कर, जमानत मिल चुकी है।वर्तमान प्रकरण में, अपीलकर्ता के विरुद्ध कुल 11 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जैसा कि ऊपर कंडिका 3 में बताया गया है।अन्य सभी मामलों में अपीलकर्ताओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र बहुत बड़ा है, जिसमें 4 लाख से अधिक पृष्ठ हैं और 736 साक्षीयों हैं।इसके अतिरिक्त, 17 बक्सों में ऐसे दस्तावेज़ हैं जिन

पर अभी भरोसा नहीं किया गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा आवश्यक समझे जाने पर इन्हें बाद में रिकॉर्ड में लाया जा सकता है।संपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही पहले ही एनसीएलटी द्वारा शुरू की जा चुकी है और सीआईआरपी (संपत्ति सत्यापन प्रक्रिया) जारी है।वर्तमान प्रकरण में, विचारण लंबित है, न्यायालय द्वारा अभी तक आरोप निर्धारित नहीं किए गए हैं।

25. इस प्रकार, साक्षीयों की संख्या और न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि यदि मामले को प्रतिदिन के आधार पर लिया जाए, तो दो से तीन वर्षों में भी निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है।मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अपीलकर्ताओं के भारत से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इन अपीलों का निराकरण करते हुए, हम अपीलकर्ताओं को निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करना उचित समझते हैं।

25. यह प्रक्रिया के आधार पर दंड है, न कि प्रमाण के आधार पर।जैसा कि कपिल वधावन बनाम सीबीआई (उपरोक्त) प्रकरण में कहा गया है, "विचारण–पूर्व अन्वेषण पूरी होने के बाद दंड बन जाती है।"**मनीष सिसोदिया बनाम ईडी, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1920 और के.ए. नजीब बनाम** यूओआई, (2021) 3 एससीसी 713 के मामले में, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया :53. न्यायालय ने आगे टिप्पणी किया है कि समय के साथ, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने विधि के एक बहुत ही सुस्थापित सिद्धांत को भुला दिया है कि जमानत को दंड के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए।हमारे अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय जमानत देने के प्रकरण में सुरक्षित रहने का प्रयास करते हैं।जमानत एक नियम है और इनकार अपवाद है, इस सिद्धांत का कई बार उल्लंघन किया जाता है।स्पष्ट प्रकरण में भी जमानत न मिलने के कारण, इस न्यायालय में लंबित प्रकरण की संख्या बहुत अधिक है।अब समय आ गया है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय इस सिद्धांत को स्वीकार करें कि "जमानत नियम है और कारावास अपवाद है"।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

54. वर्तमान प्रकरण में, ईडी और सीबीआई दोनों ही प्रकरण में 493 साक्षी के नाम दर्ज किए गए हैं। इस प्रकरण में हजारों पन्नों के दस्तावेज़ और एक लाख से अधिक पन्नों के डिजिटल दस्तावेज़ शामिल हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि निकट भविष्य में विचारण के पूरा होने की दूर–दूर तक कोई संभावना नहीं है। हमारी राय में, विचारण के शीघ्र समापन की उम्मीद में अपीलकर्ता को अनिश्चित काल तक जेल में रखना, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा।जैसा कि बार–बार देखा गया है, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले लंबे समय तक कारावास को बिना विचारण के दंड के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

55. जैसा कि इस न्यायालय ने गुडिकंती नरसिम्हुलु (उपरोक्त) प्रकरण में देखा है, किसी व्यक्ति को विचारण या अपील के निराकरण तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने का उद्देश्य विचारण में कैदी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है।

56. वर्तमान प्रकरण में, अपीलकर्ता की समाज में गहरी जड़ें हैं।उसके देश से बाहर होने और विचारण का सामना करने के लिए अनुपलब्ध होने की कोई संभावना नहीं है।किसी भी स्थिति में, राज्य की चिंताओं को दूर करने के लिए शर्तें लगाई जा सकती हैं।"

VIII. स्व**र्णिम सिद्धांत: जमानत, जेल नहीं – शर्तों द्वारा समर्थित**

26. राजस्थान राज्य बनाम बालचंद के प्रकरण में, (1977) 4 एससीसी 308:"मूल नियम जमानत है, कारावास नहीं।"पी. चिदंबरम बनाम ईडी, (2020) 13 एससीसी 791 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया :23. कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन और अन्य(2004) 7 एससीसी 528 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया : ––

"11. जमानत देने या अस्वीकार करने के संबंध में विधि सुस्थापित निर्धारित किया गया है।जमानत देने वाले न्यायालय को अपने विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए, न कि मनमाने ढंग से।"यद्यपि जमानत देने के चरण में साक्ष्यों की विस्तृत जांच और मामले की योग्यता के विस्तृत दस्तावेजीकरण की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी ऐसे आदेशों में प्रथम दृष्टया जमानत देने के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक है, विशेषकर तब जब आरोपी पर गंभीर अपराध का आरोप हो।ऐसे कारणों से रहित कोई भी आदेश विवेकहीन माना जाएगा।जमानत देने से पहले न्यायालय के लिए अन्य परिस्थितियों के साथ–साथ निम्नलिखित कारकों पर भी विचार करना आवश्यक है:

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(क) अभियोग की प्रकृति, दोष सिद्ध होने पर दंड की गंभीरता और सहायक साक्ष्यों की प्रकृति।

(ख) साक्षी के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या परिवादी को धमकी की आशंका।

(ग) आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि।(देखें :––राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह (2002) 3 एस. सी. सी. 598 तथा पूरन बनाम रामबिलास (2001) 6 एस. सी. सी. 338 ।)जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल बनाम तमिलनाडु राज्य (2005) 2 एससीसी 13 में जमानत देने के लिए विचार किए जाने वाले कारकों का उल्लेख करते हुए, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :

"16. .....गैर–जमानती अपराधों में जमानत देते समय न्यायालय द्वारा सामान्यतः जिन बातों पर विचार किया जाता है, उन्हें इस न्यायालय ने स्टेट बनाम कैप्टन जगजीत सिंह (ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 253) और गुरचरण सिंह बनाम स्टेट (दिल्ली प्रशासन) (1978) 1 एस. सी. सी 118 के मामलों में स्पष्ट किया है, और मूलतः वे इस प्रकार हैं:

— अपराध की प्रकृति और गंभीरता; साक्ष्य का स्वरूप; आरोपी से संबंधित विशिष्ट परिस्थितियाँ; विचारण के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित न होने की उचित संभावना; गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका; जनता या राज्य का व्यापक हित और अन्य समान कारक जो प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में सुसंगत हो सकते हैं..."

XXXXXXXXXXXXXXX

30. माननीय सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि साक्षी 'एक्स' ' का बयान, जिसे कथित तौर पर अपीलकर्ता और उसके बेटे के बारे में कोई भी जानकारी प्रकट न करने के लिए संपर्क किया गया था, धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें उक्त साक्षी 'एक्स' ने यह बयान दिया है कि उसे संपर्क किया गया था।सीआरपीसी कि धारा 164 के तहत उक्त साक्षी 'एक्स' के बयान 15.03.2018 को दर्ज किया गया था।उक्त साक्षी, या इस तरह के मामले में अन्य साक्षी से कथित तौर पर संपर्क किया गया था, उसे देहाती या कमजोर साक्षी नहीं कहा जा सकता है, जिसे इतनी आसानी से प्रभावित किया जा सके; विशेषकर तब जब आरोप दस्तावेजों पर आधारित बताए जा रहे हों।विशेष रूप से, ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि अपीलकर्ता या उसके आदमियों ने उक्त साक्षी से संपर्क किया था ताकि उसे अपीलकर्ता या उसके बेटे के विरुद्ध बयान न देने के लिए प्रभावित किया जा सके।"

27. इस प्रकार वह प्रस्तुत करता है कि जैसा कि ऊपर सूचीबद्ध किया गया है – जहां गिरफ्तारी दुर्भावना से प्रेरित है, अन्वेषण त्रुटिपूर्ण है, समानता के लिए समता का आह्वान किया जा रहा है, त्रिगुण परीक्षण का उल्लंघन हो रहा है, और अनुच्छेद 21 के तहत दी गई स्वतंत्रता खतरे में है – ऐसे में न्यायालय कृपापूर्वक आवेदक को उचित समझे जाने वाली शर्तों पर तत्काल नियमित जमानत प्रदान करने की कृपा करे।कोई अन्य प्रभावी उपाय उपलब्ध नहीं है।इसलिए मैंने इसी के अनुरूप प्रार्थना की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरदायी/राज्य के स्वयं के बारे में निवेदन:--

28. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क के जवाब में निम्नलिखित बिंदुवार उत्तर प्रस्तुत किया है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि आवेदक – कथित सरगना और 4000 करोड़ रुपये से अधिक के शराब सिंडिकेट का प्रमुख लाभार्थी – चल रही जांच के लिए एक गंभीर खतरा क्यों है और उसे निरंतर हिरासत में रखने का हकदार क्यों है:

I. दुर्भावनापूर्ण गिरफ्तारी/"एवरग्रीनिंग" – एक निराधार झूठ; साक्ष्यों को मोड़ने के साथ गिरफ्तारी का समय बिल्कुल सटीक था।

29. आवेदक द्वारा "बीमा गिरफ्तारी" का वर्णन निर्विवाद जांच घटनाक्रम का जानबूझकर विकृत रूप है। अनाम या हाशिए पर होने के बजाय, पांच पूरक आरोपपत्रों के बाद सामने आए साक्ष्यों के माध्यम से आवेदक इस घोटाले के मुख्य सूत्रधार के रूप में उभरता है।आरोपपत्र संख्या 03/2024 (01.07.2024, पृष्ठ 239) में आवेदक के धन के प्रवाह के संबंध में प्रारंभिक सुराग थे; आरोपपत्र के बाद के बयानों (प्रोबीर शर्मा दिनांक 04.12.2025; लक्ष्मीनारायण बंसल) + बैंकिंग साक्ष्यों के माध्यम से पूर्ण दोष सिद्ध हुआ, जो आवेदक के निर्देशों पर ₹1000+करोड़ जमा किए जाने की पुष्टि करते हैं।24.09.2025 को गिरफ्तारी इस माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत खारिज किए जाने के बाद हुई (24.09.2025) –

न कि ईडी की 60 दिन की समय सीमा के बाद – 2 घंटे की पूछताछ (12.09.2025) के बाद जिसमें असहयोग और टालमटोल की रणनीति का पता चला।जहां अभिरक्षा में आमना–सामना अनिवार्य है, वहां धारा 41ए बीएनएसएस के तहत नोटिस की आवश्यकता नहीं है (सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2022) 1 एससीसी 676, जिसमें निम्नलिखित निर्णय दिया गया है:"

19. ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान विशेष न्यायाधीश इस गलत धारणा के शिकार थे कि प्रत्येक गैर–जमानती और संज्ञेय अपराध में पुलिस को अनिवार्य रूप से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक है, भले ही यह अन्वेषण के उद्देश्य से आवश्यक न हो।

20. बल्कि विधि इसके विपरीत है।सामान्य परिस्थितियों में पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजने से सदैव बचना चाहिए, यदि पुलिस के लिए उसकी गिरफ्तारी के बिना अन्वेषण पूरी करना संभव हो और यदि आरोपी अन्वेषण अधिकारी को अन्वेषण पूरी करने में हर तरह का सहयोग प्रदान करे।केवल अत्यंत आवश्यक मामलों में ही, जहां किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए बिना अन्वेषण पूरी नहीं की जा सकती है, उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपराध से संबंधित आपत्तिजनक वस्तुओं या हथियार के सुराग की बरामदगी के लिए या उसके सहयोगियों या किसी परिस्थितिजन्य साक्ष्य से कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकती है।ऐसी गिरफ्तारी तब भी आवश्यक हो सकती है जब संबंधित अन्वेषण अधिकारी या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को लगता है कि अपराध की गंभीरता और जोखिम के कारण आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना कठिन होगा, क्योंकि उसके फरार होने, प्रक्रिया का उल्लंघन करने या न्याय से भागने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. हम उच्च न्यायालयों के उपरोक्त मत से सहमत हैं और उक्त न्यायिक दृष्टिकोण को अपनी प्रमुखता देना चाहते हैं।सीआरपीसी की धारा 170 पर विचार करने पर यह सही पाया गया है कि यह प्रभारी अधिकारी पर आरोपपत्र दाखिल करते समय प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने का दायित्व नहीं डालती है।वास्तव में, हमारे सामने ऐसे मामले आए हैं जहां आरोपी ने पूरी अन्वेषण में सहयोग किया है और फिर भी आरोपपत्र दाखिल होने पर उसकी गिरफ्तारी और न्यायालय के समक्ष पेशी के लिए गैर–जमानती वारंट जारी किए गए हैं, जिसका आधार यह है कि आरोपी को गिरफ्तार करना और उसे न्यायालय के समक्ष पेश करना अनिवार्य है।हमारा विचार है कि यदि अन्वेषण अधिकारी को यह विश्वास नहीं है कि आरोपी फरार हो जाएगा या समन का उल्लंघन करेगा, तो उसे हिरासत में पेश करने की आवश्यकता नहीं है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 में प्रयुक्त शब्द ""अभिरक्षा"" का तात्पर्य न तो पुलिस हिरासत से है और न ही न्यायिक हिरासत से, बल्कि इसका तात्पर्य केवल जांच अधिकारी द्वारा आरोपपत्र दाखिल करते समय आरोपी को अदालत के समक्ष पेश करने से है।

10. हम यह ध्यान दे सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक दायित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अन्वेषण के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार करने का अवसर तब उत्पन्न होता है जब अभिरक्षा में अन्वेषण आवश्यक हो जाती है, या यह एक जघन्य अपराध होता है, या जहां साक्षी को प्रभावित करने की संभावना होती

है या आरोपी के फरार होने की आशंका होती है।केवल इसलिए कि गिरफ्तारी वैध है, इसका अर्थ यह नहीं है कि गिरफ्तारी अनिवार्य है।गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर करना आवश्यक है।यदि गिरफ्तारी को नियमित प्रक्रिया बना दिया जाए, तो इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपार क्षति पहुँचती है।यदि अन्वेषण अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण न हो कि आरोपी फरार हो जाएगा या समन का उल्लंघन करेगा, और वास्तव में उसने पूरी अन्वेषण में सहयोग किया हो, तो हमें यह समझ में नहीं आता है कि अधिकारी पर आरोपी को गिरफ्तार करने का दबाव क्यों होना चाहिए।"

30. जहां अन्वेषण के दौरान गिरफ्तारी की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है, वहां नोटिस देना अनिवार्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का जोगिंदर कुमार (1994) 4 एससीसी 260 का प्रकरण सामान्य मामलों पर लागू होता है, न कि ₹4000 करोड़ के मेगा–घोटालों पर, जहां वित्तीय साक्ष्यों की अन्वेषण के लिए अभिरक्षा में रखकर विश्लेषण की आवश्यकता होती है (निम्मगड्डा प्रसाद बनाम सीबीआई, (2013) 7 एससीसी 466), इसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया हैः

(22) यह भी बताया गया है कि मेसर्स इंडस टेकज़ोन प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 75 एकड़ भूमि को गिरवी रखकर 175 करोड़ रुपये का ऋण लिया, जिसे परियोजना के विकास के लिए खर्च किया गया दिखाया गया है। अन्वेषण एजेंसी का मानना है कि धनराशि का एक बड़ा हिस्सा फर्जी कार्य आदेशों/आरए बिलों के माध्यम से गबन/दुरुपयोग किया गया था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. आर्थिक अपराधों के लिए जमानत की कड़ी जांच आवश्यक है।अरविंद केजरीवाल (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 2550) ने अंतर बताया:वहाँ, संज्ञान से पहले की गिरफ्तारी; यहाँ, आरोपपत्रों और साक्षी के बयानों के बाद की गिरफ्तारी।

II:धारा 35(ख) बीएनएसएस निधि का पता लगाने और आमना–सामना करने के लिए अभिरक्षा की अनिवार्यता को पूरी तरह से संतुष्ट करता है:रिमांड के आधार(24.09.2025–06.10.2025) धारा 35(ख) को स्पष्ट रूप से संतुष्ट करते हैं:उनका कहना है कि दस्तावेजी वित्तीय घोटाले में वसूली की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी बनाम सीबीआई, (2013) 7 एससीसी 439 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है, जिसमें यह देखा गया है कि "धन के मार्ग का पता लगाने के लिए अभिरक्षा आवश्यक है, न कि भौतिक वसूली"।

III:आगे की अन्वेषण पूरी तरह से वैध है – आरोप पत्र की क्रमिक स्वीकृति के माध्यम से स्वीकृत अनुमति।

32. आवेदक का "शुरू से ही अमान्य" होने का तर्क न्यायिक मिसाल और इस न्यायालय के स्वयं के आदेशों द्वारा खारिज कर दिया गया है:न्यायिक स्वीकृतिःविशेष न्यायालय ने बिना किसी आपत्ति के सभी 6 आरोपपत्रों (मुख्य + 5 पूरक) को स्वीकार कर लिया – स्पष्ट रूप से अनुमति मान ली गई (अनिल तुतेजा एसएलपी (सीआरएल) 11659/2024 खारिज 16.09.2025)।आवेदक का दमनःसीआर.एम.पी. 2654/2025 (आगे की जांच को चुनौती देते हुए) इस न्यायालय द्वारा 28.08.2025 को विचारणीयता के आधार पर

खारिज कर दिया गया, नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई – कभी दायर नहीं की गई। अनुलग्नक– दमन को साबित करता है – प्रक्रिया के दुरुपयोग की बू आती है।सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व निर्णय: विनय त्यागी (2013) 5 एससीसी 762, जिसमें अनौपचारिक सूचना की अनुमति दी गई है। यह अभिनिर्धारित किया गया है किः

49. इसके विपरीत, न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि यह पूरक या आगे की अन्वेषण और 'पूरक रिपोर्ट' दाखिल करने का प्रकरण था।

50. एक बार न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपना लिया है, तो पहली रिपोर्ट को वापस लेने, रद्द करने या अप्रत्यक्ष रूप से अभिलेखों से बाहर करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वास्तव में, उक्त आदेश देने के लिए सक्षम उच्च न्यायालय के विशिष्ट आदेश को छोड़कर, पिछली और पूरक रिपोर्ट दोनों ही अभिलेखों का हिस्सा होंगी, जिन पर निचली अदालत से कानून के अनुसार उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विचार करने की अपेक्षा की जाती है।यह भी दिलचस्प है कि सीबीआई ने स्वयं अदालत के आदेश को समझा और केवल 'आगे की अन्वेषण' की, जैसा कि सीबीआई द्वारा 28 नवंबर, 2007 को उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई स्थिति रिपोर्ट से स्पष्ट है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रॉबर्ट लालचुंगनुंगा (2025) के मामले में स्वीकृत आरोपपत्रों को पूर्वव्यापी रूप से अमान्य नहीं किया गया है। आवेदक चैतन्य बघेल (17.10.2025) का वर्तमान मामला इससे भिन्न है:इसमें आरोपपत्र की स्वीकृति नहीं है; पूर्ण न्यायिक संज्ञान लिया गया है।

IV:समता अप्रभावी –नाबालिगों को जमानत; सर्वोच्च न्यायाल ने सरगनाओं की जमानत याचिका खारिज की

33. आवेदक द्वारा चुनी गई सूची इस न्यायालय को गुमराह करती है:

वास्तविक स्थिति:जमानत पर रिहा किए गए 22 में से 12 नाबालिग अपराधी हैं;मुख्य आरोपी (जैसे आवेदक) ने इनकार किया (विपिन यादव का मामला अलग है – इसमें ₹4000 करोड़ का घोटाला नहीं है)। लक्ष्मीनारायण बंसल:गिरफ्तारी से पहले स्वेच्छा से सहयोग किया (22.05.2025 को जांच में सहायता के लिए एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था, न कि विचारण के लिए);रद्द करने के लिए आवेदन लंबित है – धारा 72 का उल्लंघन नहीं हुआ है (सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) 1 एससीसी 676 कंडिका18:"सहयोग यांत्रिक गिरफ्तारी को रद्द कर देता है")।

V:ट्रिपल टेस्ट उम्मीद के मुताबिक विफल–आवेदक हर मानदंड में विफल रहा

34. उत्तरवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक जमानत देने के लिए निर्धारित "त्रिस्तरीय परीक्षण" के प्रत्येक पहलू में घोर रूप से विफल है।उसकी हैसियत, संसाधन और आचरण उसे तीनों ही मामलों में एक उच्च जोखिम वाला आरोपी बनाते हैं—भागने का जोखिम, साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना और गवाहों को प्रभावित करने या डराने की प्रवृत्ति।कृष्णा मोची बनाम बिहार राज्य (2002) 6 एससीसी 81

के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी है कि शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से जुड़े आरोपी अक्सर साक्षीयों को डराते–धमकाते हैं, जिससे बयान वापस लेने, शत्रुता और अभियोजन के विफल होने की स्थिति उत्पन्न होती है।वर्तमान प्रकरण उस सिद्धांत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है:आवेदक की अपार वित्तीय शक्ति और गहरे राजनीतिक–नौकरशाही संबंध, साथ ही प्रमुख साक्षीयों पर दबाव डालने के विशिष्ट आरोप, न्याय की उचित प्रक्रिया में हस्तक्षेप का एक स्पष्ट, तात्कालिक और असहनीय जोखिम पैदा करते हैं, जिससे वह जमानत जैसी विवेकाधीन राहत का हकदार नहीं रह जाता है।यह कहा गया है कि आरोपी शक्तिशाली है और साक्षीयों को डराता–धमकाता है।

VI:प्रथम दृष्टया प्रबल प्रकरण – आवेदक निर्विवाद रूप से मुख्य आरोपी है

35. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभिलेख पर मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया एक प्रबल मामला प्रकट करती है, जो आवेदक को साजिश के प्रमुख सरगनाओं में से एक के रूप में दृढ़ता से स्थापित करती है।साक्ष्यों का आधार अकाट्य और बहुआयामी है:प्रोबीर शर्मा का बयान (धारा 161 बीएनएसएस, दिनांक 04.12.2025):उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि आवेदक के कहने पर लगभग ₹70 करोड़ की राशि पप्पू बंसल के माध्यम से विजय अग्रवाल को भेजी गई थी, जिससे प्रत्यक्ष रूप से नाम और धन के लेन–देन का ठोस प्रमाण मिलता है। लक्ष्मीनारायण बंसल का कथन :उन्होंने आगे खुलासा किया है कि घोटाले की लगभग 1000 करोड़ रुपये की रकम आवेदक के विशेष निर्देशों पर राम गोपाल अग्रवाल के पास जमा की गई थी, जो एक बार फिर आवेदक को अवैध धन के अंतिम गंतव्य से जोड़ती है।बैंक अभिलेख तथा खाते:शिवम कंस्ट्रक्शंस के खातों में बड़ी मात्रा में अस्पष्ट नकदी जमा दिखाई देती है, जो समय और मात्रा के हिसाब से शराब घोटाले से प्राप्त आय के समान है।प्रमुख इकाई :विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट और बघेल जैसे प्रोजेक्ट्स को लेकर चिंताएं हैं।डेवलपर्स फर्जी या दिखावटी संस्थाओं के रूप में सामने आए हैं, जिन्हें आवेदक के इशारे पर भ्रष्ट धन को छिपाने और उसका दुरुपयोग करने के लिए बनाया गया था।मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की यह पुष्ट श्रृंखला हरिचरण कुर्मी और निम्मागड्डा प्रसाद बनाम सीबीआई मामले में निर्धारित सीमा को पूरा करती है, जिससे जमानत के चरण में किसी भी प्रकार के संक्षिप्त विचारण की आवश्यकता नहीं रह जाती है।अत: प्रारंभिक चरण में भी अपराधों के वैधानिक तत्व स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाते हैं:आई. पी. सी. की धारा 120–बी:धन के समन्वित प्रवाह और भंडारण से एक सामान्य योजना स्पष्ट होती है, जो कई वर्षों से लागू किए गए एक साझा आपराधिक करार को दर्शाती है। आई. पी. सी. की धारा 420,467,468,471:धोखाधड़ी की योजना के तहत आवेदक के नेटवर्क के माध्यम से जाली होलोग्राम और संबंधित मनगढ़ंत दस्तावेज़ तैयार किए गए और भेजे गए।भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12:अभिलेख से पता चलता है कि आवेदक और उसके सहयोगियों के लाभ के लिए काम करने वाले राजनीतिक और आधिकारिक अभिकर्ताओं के गठजोड़ के माध्यम से भ्रष्टाचार के कृत्यों को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा दिया गया था।आसन्न; आवेदक के कारण विलंब। अत:, आवेदक की अभिरक्षा जारी रखने में अनुच्छेद 21 का कोई उल्लंघन नहीं है।अन्वेषण पूरा होने के करीब है:छह आरोपपत्र पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं; लगभग 885 गवाह और 939 दस्तावेज़ एकत्रित कर लिए गए हैं और विचारण में सबूत के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तौर पर पेश किए जाने के लिए तैयार हैं।मामूली देरी का मुख्य कारण आवेदक की अपनी कानूनी रणनीति है, जिसमें 12.09.2025 से 24.09.2025 के बीच अग्रिम जमानत के लिए चली लंबी प्रक्रिया भी शामिल है, जिसके कारण न्यायिक और जांच का समय स्वाभाविक रूप से खर्च हुआ।

VII:जमानत, जेल नहीं; यह नियम सरगनाओं पर अप्रभावी नहीं है

36. यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक की "एफआईआर/चार्जशीट में नाम नहीं होने" के तर्क:

आवेदक द्वारा मामूली संलिप्तता के संकेत के विपरीत, बीएनएसएस कि धारा 173(8) के तहत आरोप पत्र दाखिल करने के बाद की जांच ने उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट कर दिया:प्रोबीर शर्मा (सीआरपीसी कि धारा161 दिनांक 04.12.2025):"आवेदक ने लक्ष्मीनारायण बंसल के माध्यम से विजय अग्रवाल को ₹270 करोड़ की धनराशि भेजने का षड्यंत्र रचा"—धन के लेन–देन का सीधा खुलासा।लक्ष्मीनारायण बंसल:"आवेदक के स्पष्ट निर्देशों पर फरार राम गोपाल अग्रवाल (छत्तीसगढ़ कांग्रेस कोषाध्यक्ष) के पास 1000 करोड़ रुपये जमा हैं।"बैंक लेजर (विट्ठलपुरम आवासीय परिसर):करोड़ों रुपये की अस्पष्ट नकद जमा राशि घोटाले की आय को दर्शाती है; निर्माण पर नकद व्यय ने धन शोधन को छुपाया (जैसे, कैजुअल जूते–3, सैंडल–2, चप्पल–2, तौलिए–21)।ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक, (1988) 2 एस. सी. सी. 602 (कंडिका 133):अभियोजन पक्ष एफआईआर में सभी आरोपियों का नाम दर्ज करने के लिए बाध्य नहीं है; वे साक्षी के रूप में परीक्षा कर सकते हैं।संयुक्त सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है।लक्ष्मीपत चोरारिया बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1968 एससी 938 :सह–अपराधी साक्ष्य (साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 के तहत संरक्षित) सावधानी के साथ स्वीकार्य है—सटीक रूप से लागू होता है।2.आवेदक की भूमिकाःमुख्य सूत्रधार और सर्वोत्कृष्ट वास्तुकार (मामूली खिलाड़ी नहीं) आवेदक की केंद्रीयता समानता के दावों को ध्वस्त कर देती है।उन्होंने घोटालेबाजी तंत्र की निगरानी की (2019–2023):अवैध रूप से बिना शुल्क वाली शराब का उत्पादन; शराब बनाने वाली भट्टियों के मालिकों से कमीशन।होलोग्राम की जालसाजी; सरकारी दुकानों में विक्रय; भाग–बी के तहत धन की हेराफेरी।सुनियोजित नीतिगत विध्वंसःएफ. एल./आई. एम. एफ. एल.आयोगों के लिए अनुकूलित उत्पाद शुल्क नीति; पार्ट–बी लूट के लिए जनशक्ति एजेंसियां; रणनीतिक अधिकारी नियुक्तियां; उनके अधीन जिला स्तरीय "संपर्क व्यक्ति"।वित्तीय तंत्रिका केंद्रःअवैध आय का लेखा–जोखा; शेल संस्थाओं (विट्ठलपुरम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, शिवम कंस्ट्रक्शंस) के माध्यम से धन का शुद्धिकरण – ₹4000 करोड़ का सरकारी खजाना घाटा, सिंडिकेट का लाभ।गुलाबराव बाबूकर देवकर बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2013) 16 एससीसी 190:जमानत राशि निर्धारित करते समय आर्थिक अपराध की प्रकृति/गंभीरता और सामाजिक प्रभाव सर्वोपरि होते हैं।बैंक प्रविष्टियाँ प्रत्यक्ष निवेश की पुष्टि करती हैंःविट्ठलपुरम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के खातों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बड़ी मात्रा में, अस्पष्ट नकद प्राप्तियों के माध्यम से दूषित धन का प्रवाह हुआ है – जो समय/मात्रा के हिसाब से घोटाले की वसूली से मेल खाता है।नकदी को असुरक्षित ऋणों/अग्रिम भुगतानों/फर्जी रसीदों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और प्राप्त आय को अचल संपत्ति में निवेश किया जाता है।आवेदकःप्रमुख लाभार्थी तथा धनशोधनकर्ता।3. "कोई तलाश/पुनर्प्राप्ति नहीं "रेड

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हेरिंग:वित्तीय घोटालों में असंगत: दस्तावेजी धन शोधन रैकेट में भौतिक बरामदगी का कोई महत्व नहीं है: ईडी खोज (18.07.2025):स्तरित धनशोधन की पुष्टि करने वाले बैंक दस्तावेज/खाते।ईओडब्ल्यू रिमांड (24.09.2025–06.10.2025):असहयोग का खुलासा +अभिरक्षा में टकराव; गवाहों को धमकाना (पुनर्प्राप्ति नहीं)।वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी बनाम सीबीआई, (2013) 7 एस.सी.सी. 439 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभिरक्षा वित्तीय ट्रेल्स को डिकोड करती है, न कि ज़ब्ती प्रदान करती है। 4.न्यायिक रूप से आगे की अन्वेषण को मंजूरी दे दी गई है और आरोपपत्र स्वीकार कर लिए गए हैं।

37. आवेदक की "शुरू से ही अमान्य" होने की तर्क खारिज कर दी गई।विशेष न्यायालय ने बिना किसी आपत्ति के मान्य अभियोगपत्र (मुख्य अभियोग और 5 पूरक अभियोगपत्र) स्वीकार कर लिए;धारा 173(8) बीएनएसएस के तहत अनुमति निहित मानी गई।आवेदक की सीआर.एम.पी. संख्या 2654/2025 खारिज (28.08.2025) – तथ्यों को छिपाना प्रक्रिया का दुरुपयोग साबित करता है।अनिल टुटेजा की एसएलपी खारिज (16.09.2025); चैतन्य बघेल से भिन्न (वहां आरोप पत्र स्वीकार नहीं किया गया था)। विनय त्यागी बनाम इरशाद अली, (2013) 5 एससीसी 762 (कंडिका 49):

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनौपचारिक सूचना पर्याप्त है।5.समानता भ्रमःसह–अभियुक्त नाबालिगों को जमानत दी गई; गिरोह को 12/22 से इनकार किया गयाःछोटे लॉजिस्टिक्स हैंडलर/संचालकमुख्य वित्तपोषक (आवेदक स्तर) जेल में बंद हैं।6. तिहरा परीक्षण बुरी तरह विफल रहा—जांच के लिए अस्तित्वगत खतरा; भागने का जोखिम:अघोषित विदेशी संपत्ति (शिवम कंस्ट्रक्शंस); राजनीतिक पलायन नेटवर्क।छेड़छाड़ का जोखिमःप्रोबीर शर्माः"आवेदक ने ईडी की गिरफ्तारी के बाद धमकी दी; दस्तावेज में हेरफेर किया गया।प्रभाव जोखिमःलक्ष्मीनारायण बंसलः"संबंधी ने दबाव डाला "; राम गोपाल अग्रवाल फरार हो गए।वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी (2013) 7 एस. सी. सी. 439 (कंडिका 42):प्रभावशाली आरोपी सत्यनिष्ठा को खतरे में डाल रहे हैं?जमानत देने से इनकार कर दिया।कृष्ण मोची बनाम बिहार राज्य, (2002) 6 एस. सी. सी. 81 (कंडिका 31):शक्तिशाली अभियुक्त साक्षीयों को पंगु बना देता है।लक्ष्मीनारायण बंसलःस्वैच्छिक सहयोग (एनबीडब्ल्यू जांच सहायता); रद्द करना लंबित (सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2022) 1 एससीसी 676 कंडिका 18)।7.प्रथम दृष्टया प्रकरण पुख्ता है:हरिचरण कुर्मी की चेतावनी से परे, पुष्ट वित्तीय मैट्रिक्स:प्रत्यक्ष वक्तव्यःप्रोबीर शर्मा + लक्ष्मीनारायण बंसल (नामकरण मात्रा)।वृत्तचित्र की आधारशिला:बैंक प्रविष्टियाँ + बहीखाते (₹1000 करोड़ का पता लगाया गया)।नीति में हेरफेरःउत्पाद शुल्क नीति + निविदा में धांधली (आवेदक की उंगलियों के निशान)।आई. पी. सी/पी. सी. सामग्रीःधारा120 बी:सिद्ध सामान्य डिजाइन (जिला संपर्क ग्रिड)।धारा 420/467/468/471:होलोग्राम जालसाजी उकसाना; वितरण आगे बढ़ता है।पीसी कि धारा 7/12:राजनीतिक–आधिकारिक सांठगांठ। निम्मगड्डा प्रसाद बनाम सी. बी. आई. (2013) 7 एस. सी. सी. 466:वित्तीय निशान = प्रथम दृष्टया दोष सिद्ध। 8. अनुच्छेद 21 का कोई उल्लंघन नहींजनहित विलंब से अधिक महत्वपूर्ण है। मुकदमा जल्द ही शुरू होने वाला है (आरोपपत्र पूर्ण हो चुके हैं); विलंब स्वयं के कारण हुआ है (अग्रिम जमानत श्रृंखला)।के. ए. नजीब

(पीएमएलए–विशिष्ट); कपिल वधावन (2025 आई. एन. एस. सी. 1440):जारी आर्थिक अन्वेषण देरी को दरकिनार करती है।

9.जमानत संबंधी नियम लागू नहीं:"गिरोह अपवाद" संजय चंद्र/पी. चिदंबरम का शासन:जांच पूरी हो गई है। यहां, लाइव अन्वेषण से कई परतें खुलती हैं।राजस्थान राज्य बनाम बालचंद मामला: ₹4000 करोड़ के सामाजिक विनाश से संबंधित प्रकरण ।

38. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में—पुष्टि किए गए वित्तीय लेन–देन के माध्यम से प्रथम दृष्टया सरगना की भूमिका स्थापित होती है; त्रिपक्षीय परीक्षण बुरी तरह विफल होता है; समानता भ्रामक है; आगे की जांच के लिए निरंतर हिरासत की आवश्यकता है और इसलिए, कृपया आवेदन को खारिज कर दें और दिनांक 08.10.2025 के विवादित आदेश को बरकरार रखें।सार्वजनिक हित निजी स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है ।

VIII. बैंक प्रविष्टियाँ स्कैम प्रक्रियाओं के निर्देशन तथा उपयोग की स्थापना करती हैं

39. यह विशेष रूप से दोहराया जाता है कि आवेदक की फर्म, विट्ठलपुरम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के बैंक खाते की प्रविष्टियाँ स्पष्ट रूप से बड़ी, अस्पष्ट नकद प्राप्तियों के बदले में दूषित धन के प्रवाह को स्थापित करती हैं।नकदी का यह प्रवाह, समय और मात्रा दोनों ही दृष्टि से, शराब घोटाले से प्राप्त और गिरोह के माध्यम से भेजी गई नकदी से मेल खाता है।अन्वेषण से पता चला है कि इस तरह की नकदी को व्यवस्थित रूप से असुरक्षित ऋणों, अग्रिमों या फर्जी व्यावसायिक रसीदों के बहाने बैंकिंग प्रणाली में डाला गया था, जिससे अपराध की आय को आवेदक की अचल संपत्ति परियोजना में एकीकृत किया गया था।ये तथ्य आवेदक के स्वयं को मात्र एक दर्शक के रूप में प्रस्तुत करने के प्रयास को निष्फल साबित करते हैं और इसके बजाय मुख्य लाभार्थी और धन शोधनकर्ता के रूप में उसकी भूमिका को पुष्ट करते हैं।आवेदक ने इन अघोषित आय का उपयोग अपने निजी प्रोजेक्ट के लिए वस्तुओं, सेवाओं और निर्माण संबंधी भुगतानों के वित्तपोषण में किया, जिससे न केवल काले धन को वैधता मिली बल्कि राज्य को कर और उत्पाद शुल्क राजस्व का भी भारी नुकसान हुआ।ये कृत्य अपराध की आय के सृजन, स्तरीकरण और एकीकरण के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो आर्थिक अपराध न्यायशास्त्र की कठोरता को स्पष्ट रूप से आकर्षित करते हैं, जैसा कि **निम्मगड्डा प्रसाद बनाम सीबीआई, (2013) 7 एससीसी 466 और गुलाबराव देवकरबनाम महाराष्ट्र राज्य, (2013) 16 एससीसी 190 में मान्यता प्राप्त है।**

2.साक्षी के बयान आवेदक के खिलाफ एक सुसंगत, पुष्ट श्रृंखला बनाते हैं

2.1 आवेदक का यह दावा कि "कोई सामग्री नहीं है" या केवल "स्पष्ट बयान" हैं, स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। अभियोजन पक्ष किसी एक अप्रतिबंधित बयान पर नहीं, बल्कि धारा 161 बीएनएसएस के तहत कई स्वतंत्र गवाहों द्वारा दर्ज किए गए बयानों के एक समन्वित समूह पर निर्भर करता है, जिनमें श्री प्रोबीर शर्मा भी शामिल हैं – जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आवेदक के कहने पर उन्होंने घोटाले की आय का उपयोग करके आवेदक की परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर नकदी लेनदेन और निवेश की सुविधा प्रदान की; श्री राजेश बिसन और श्री विमल कुमार तिवारी – सह–आरोपी से जुड़े कर्मचारी; उनके बयान बताते हैं कि शराब व्यापार से एकत्र की गई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नकदी को व्यवस्थित रूप से कैसे स्थानांतरित किया गया था।श्री संतोष अग्रवाल और श्री राजेंद्र कुमार अग्रवाल – जिनके साक्ष्य धन के आगे के प्रबंधन और प्रवाह पर प्रकाश डालते हैं; श्री राकेश डोधी – चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिनकी कथन तथा अभिलेख आवेदक के लिए किए गए वित्तीय संरचना को पेशेवर रूप से प्रमाणित करते हैं।

40. यदि इन कथनों को बैंकिंग अभिलेखों और बहीखातों की प्रविष्टियों के साथ पढ़ा जाए, तो ये एक सुदृढ़, परस्पर–पुष्टि करने वाली साक्ष्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं।जमानत के चरण में, कानून केवल ऐसी सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्ट्या संतुष्टि की अपेक्षा करता है; निर्णायक प्रमाण मानक नहीं है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्मगड्डा प्रसाद और वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी बनाम सीबीआई, (2013) 7 एससीसी 439 में बार–बार कहा है।

41. आवेदक द्वारा सह–अपराधी साक्ष्यों के संबंध में सावधानी बरतने के सिद्धांत पर आधारित होना वर्तमान संदर्भ में अनुचित है।राज्य अपना मामला केवल एक सह–अपराधी के बयान पर आधारित नहीं करता; बल्कि, यह परस्पर जुड़े बयानों और दस्तावेजी सामग्री पर निर्भर करता है जो सामूहिक रूप से आवेदक के दोष को स्थापित करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. साक्षीयों को व्यवस्थित रूप से डराना–धमकाना साक्ष्यों में छेड़छाड़ के वास्तविक और वर्तमान जोखिम को दर्शाता है:

अन्वेषण के दौरान, कई स्वतंत्र स्रोतों और प्रमुख साक्षीयों के बयानों से यह बात सामने आई है कि आवेदक ने अपने बेहद प्रभावशाली पिता के साथ मिलकर महत्वपूर्ण गवाहों को धमकाया, डराया और उन पर दबाव डाला ताकि वे अपने पहले के बयानों को वापस ले लें, उनमें नरमी लाएं या उनसे मुकर जाएं।यह आचरण काल्पनिक नहीं है; यह अभिलेख से प्रमाणित है।साक्षीयों ने विशेष रूप से बताया है कि मुलाकातों, फोन कॉलों और मध्यस्थों के माध्यम से उन पर किस प्रकार दबाव डाला गया, और उन्हें स्पष्ट संदेश दिया गया कि आवेदक के खिलाफ प्रतिकूल गवाही देने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

42. **कृष्णा मोची बनाम बिहार राज्य, (2002) 6 एससीसी 81** में,सर्वोच्च न्यायालय ने शक्तिशाली, राजनीतिक रूप से जुड़े आरोपी व्यक्तियों का सामना करने पर साक्षीयों की अंतर्निहित भेद्यता को मार्मिक रूप से नोट किया और चेतावनी दी कि न्यायालय को धमकी और दमन की वास्तविक संभावना को ध्यान में रखना चाहिए।वर्तमान मामला उस सिद्धांत का सटीक उदाहरण है, क्योंकि आवेदक के पास अपार वित्तीय शक्ति, राजनीतिक संबंध और पारिवारिक प्रभाव है।इन परिस्थितियों में, यह आशंका कि आवेदक साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा और साक्षीयों को धमकाएगा, अभियोजन पक्ष का मात्र आरोप नहीं है; यह एक ठोस और प्रमाणित वास्तविकता है।ऐसी स्थिति में जमानत देना दंड से मुक्ति का संदेश देगा और चल रही अन्वेषण को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगा।

43. आवेदक का आचरण उसे विवेकाधीन अनुतोष के लिए अयोग्य ठहराता है:

एकत्रित सामग्री – बैंक लेनदेन, गवाहों के पुष्ट बयान और हस्तक्षेप के दस्तावेजी प्रयास – स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि आवेदक को घोटाले से प्राप्त धनराशि से प्रत्यक्ष और पर्याप्त लाभ हुआ है; उसने अवैध धन के सृजन, स्तरीकरण और एकीकरण में सक्रिय रूप से भाग लिया है; और गवाहों पर दबाव डालकर जांच को बाधित करने, पटरी से उतारने और दूषित करने का प्रयास किया है।जमानत एक विवेकाधीन तथा न्यायसंगत अनुतोष है।जो वादी प्रक्रिया का दुरुपयोग करता है, सुसंगत तथ्यों को छुपाता है और न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है, वह अपने पक्ष में उस विवेकाधिकार का प्रयोग करने की मांग नहीं कर सकता है।आवेदक का आचरण विश्वास जगाने के बजाय न्यायिक सावधानी की मांग करता है।

44. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक की बहु–करोड़ आर्थिक अपराध में मुख्य षड्यंत्रकारी और प्रमुख लाभार्थी के रूप में भूमिका को प्रदर्शित करने वाले मजबूत प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं; साक्ष्यों से छेड़छाड़ तथा साक्षीयों को डराने–धमकाने का खतरा काल्पनिक नहीं बल्कि स्थापित है; और निष्पक्ष और प्रभावी जांच के हित, साथ ही व्यापक जनहित और राज्य हित, इस स्तर पर आवेदक की रिहाई से गंभीर रूप से प्रभावित होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

45. साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ में औपचारिक रूप से संरचित, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त राज्यव्यापी शराब घोटाला हुआ था।अन्वेषण में यह बात सामने आई है कि 2018 से 2023 के बीच, तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के कार्यकाल के दौरान, छत्तीसगढ़ में औपचारिक रूप से संरचित, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त और राज्यव्यापी शराब घोटाला किया गया था।अभिलेख में मौजूद सामग्री से पता चलता है कि नौकरशाही अधिकारी, राजनीतिक प्रतिनिधि और निजी व्यक्ति अलग–थलग अपराधियों के रूप में नहीं, बल्कि एक संगठित गिरोह के हिस्से के रूप में समन्वित, पदानुक्रमित तरीके से काम कर रहे थे।ये सभी लोग वर्तमान आवेदक की स्पष्ट स्वीकृति, जानकारी और सहमति से एकमत होकर आगे बढ़े, जिसकी पहचान मुख्य षड़यंत्रकर्ताओं में से एक और आपराधिक गिरोह के प्रमुख सूत्रधार के रूप में की गई है।साक्ष्य दर्शाते हैं कि यह घोटाला कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि कई वर्षों तक चलने वाली और पूरी उत्पाद शुल्क श्रृंखला में व्याप्त भ्रष्टाचार की एक व्यवस्थित संस्थागत योजना थी।

46. सह–षड़यंत्रकर्ताओं की भूमिकाएँ षड्यंत्र में आवेदक की केंद्रीय भूमिका को दर्शाती हैं।अन्वेषण के दौरान एकत्र किए गए बयानों और दस्तावेजों से कई महत्वपूर्ण सह–षड्यंत्रकर्ताओं की पहचान होती है, जिनकी भूमिकाएं, जब एक साथ पढ़ी जाती हैं, तो आवेदक की केंद्रीय स्थिति को रेखांकित करती हैं:ए.श्रीमती सौम्या चौरसिया – प्रारंभ में उप–विभागीय अधिकारी और बाद में आयुक्त, भिलाई–चारोदा नगर निगम के पद पर तैनात रहीं, और बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर पदोन्नत हुईं। सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण से उनकी निकटता और रणनीतिक पदों ने उन्हें घोटाले से संबंधित नीतिगत और प्रशासनिक कार्यों में एक महत्वपूर्ण कड़ी बना दिया।बी. श्री अनिल टुटेजा, आईएएस – तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व से घनिष्ठ रूप से जुड़े एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जिन्होंने प्रशासनिक दांव–पेच को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे अवैध व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकी।उनके नौकरशाही प्रभाव और

विभागीय ढाँचों तक पहुँच ने इस षड्यंत्र को सुदृढ़ और सुरक्षित बना दिया। श्री अनवर ढेबर – एक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ और रायपुर नगर निगम के तत्कालीन महापौर के भाई है। उन्होंने अवैध नकदी के संचलन के लिए एक केंद्रीय चैनल के रूप में कार्य किया, शराब बनाने की भट्टियों, सिंडिकेट प्रबंधकों और राजनीतिक लाभार्थियों के बीच समन्वय स्थापित किया।इन सभी भूमिकाओं को समग्र रूप से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि आवेदक एक आकस्मिक भागीदार नहीं था, बल्कि नौकरशाहों, राजनीतिक हस्तियों और निजी कार्यकर्ताओं से बनी एक पिरामिडनुमा कमान संरचना के शीर्ष पर बैठा था, जिनमें से प्रत्येक ऐसे कार्य कर रहा था जो अंततः उसके वित्तीय और व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करते थे।

III. घोटाले की आय के गुप्त नकद लेनदेन और वितरण में आवेदक की प्रत्यक्ष भूमिका।अन्वेषण के दौरान यह निर्णायक रूप से सामने आया है कि आवेदक ने शराब घोटाले से प्राप्त अवैध नकदी – जिसे आंतरिक रूप से "माल" कहा जाता है – की गुप्त आवाजाही सुनिश्चित की।ये धनराशि नियमित रूप से रामगोपाल अग्रवाल सहित कई व्यक्तियों के बीच पहुंचाई और ली जाती थी।

47. इस प्रकार की बड़ी संख्या में धनराशि की आवक और वसूली छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय राजीव भवन, रायपुर के माध्यम से की जाती थी।सह–आरोपी अनवर ढेबर द्वारा भेजी गई नकदी को नियमित रूप से उसके भरोसेमंद सहयोगी, दीपेंन चावड़ा द्वारा ले जाया जाता था और उसके बाद लगभग हर महीने चार बार सुबह 10:00 बजे राजीव भवन में देवेंद्र ददसेना को सौंप दिया जाता था।वितरण का यह व्यवस्थित और सुनियोजित तरीका 2019 से 2021 तक लगभग दो वर्षों तक निर्बाध रूप से जारी रहा, जिससे छिटपुट या अलग–थलग लेन–देन के बजाय एक सुव्यवस्थित, सुचारू रूप से चलने वाली आपराधिक मशीनरी के अस्तित्व का पता चलता है।आंतरिक संचार और बयानों में आवेदक का नाम बार–बार इन गतिविधियों के अंतिम नियंत्रक और लाभार्थी के रूप में सामने आता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

IX. आवेदक की परियोजना में दूषित धन का निवेश – अपराध की आय का सृजन, स्तरीकरण और एकीकरण

48. आवेदक की फर्म "विट्ठलपुरम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स" के बैंक खाते की प्रविष्टियों से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि उत्पाद शुल्क घोटाले से उत्पन्न करोड़ों रुपये विभिन्न चैनलों के माध्यम से भेजे गए और अंततः फर्म के बैंक खातों में जमा किए गए।ये जमा राशि शराब के कारोबार से प्राप्त असंरक्षित नकद संग्रह से संबंधित हैं और किसी भी वैध व्यावसायिक तर्क या दस्तावेजी स्पष्टीकरण द्वारा समर्थित नहीं हैं।आवेदक ने फिर अवैध रूप से अर्जित और धन को शुद्ध करने के बाद इन पैसों का इस्तेमाल अपनी निजी परियोजना के लिए सामान, सेवाओं और निर्माण कार्यों को वित्तपोषित करने के लिए किया।इस प्रकार का आचरण अपराध से प्राप्त धन की तीन चरणों वाली प्रक्रिया का सटीक उदाहरण है:

(i) सृजन**, (ii)** स्तरीकरण और **(iii)** ए**कीकरण:**

शराब व्यापार में भ्रष्ट कमीशन तंत्र के माध्यम से सृजन; शेल संस्थाओं, नकदी वाहकों और बिचौलियों के माध्यम से स्तरीकरण; आवेदक के स्पष्ट रूप से वैध अचल संपत्ति उद्यम में निवेश के माध्यम से एकीकरण।

प्रोबीर शर्मा, राजेश बिसन, विमल कुमार तिवारी, संतोष अग्रवाल, राजेंद्र कुमार अग्रवाल और राकेश डोंधी के बयानों से इन निष्कर्षों की पुष्टि होती है, जिनकी गवाही को बैंक और बहीखाते के रिकॉर्ड के साथ मिलाकर पढ़ने पर, आवेदक की इस घोटाले में मुख्य धन शोधनकर्ता और वित्तीय सूत्रधार के रूप में भूमिका का मजबूत प्रथम दृष्टया प्रमाण मिलता है।

X. साक्षीयों को व्यवस्थित रूप से धमकाना – छेड़छाड़ और बाधा उत्पन्न होने का गंभीर जोखिम

49. अन्वेषण के दौरान, प्रमुख साक्षीयो के बयानों सहित कई स्वतंत्र स्रोतों से यह बात सामने आई है कि आवेदक ने अपने अत्यधिक प्रभावशाली पिता के साथ मिलकर महत्वपूर्ण गवाहों को धमकाया, डराया और उन पर दबाव डाला ताकि वे अपने पहले के बयानों को वापस ले लें, उनमें नरमी लाएं या उनसे मुकर जाएं।साक्षीयों ने विशेष रूप से कहा है कि उनसे संपर्क किया गया और उन्हें अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन न करने की चेतावनी दी गई, और उन पर जांच एजेंसी के साथ अपने सहयोग को बदलने या वापस लेने के लिए दबाव डाला गया था।यह आचरण कोई अलग–थलग आरोप नहीं है, बल्कि एक सुसंगत स्वरूप है, जो जांच में बाधा डालने, उसे पटरी से उतारने और उसे दूषित करने की जानबूझकर की गई षड़यंत्र को दर्शाता है।इस प्रकार का हस्तक्षेप आपराधिक न्याय प्रणाली की मूल संरचना पर प्रहार करता है और यह दर्शाता है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह चल रही कार्यवाही की निष्पक्षता के लिए एक गंभीर, तत्काल और ठोस खतरा उत्पन्न करेगा।शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली अभियुक्तों के संदर्भ में, साक्षी को धमकाने की आशंका मात्र सैद्धांतिक नहीं बल्कि पूर्णतः न्यायसंगत है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **कृष्णा मोची बनाम बिहार राज्य (2002) 6 एससीसी 81** में कहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक का प्रभाव, आर्थिक सामर्थ्य और राजनीतिक संबंध – जमानत से जांच गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएगी।अभिलेख से पता चलता है कि आवेदक एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं और नौकरशाही और राजनीतिक हलकों में उसके गहरे संबंध हैं।पूर्व सरकार में निर्णय लेने वालों से उसकी निकटता, फ्रंट संस्थाओं पर उसका नियंत्रण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में हेरफेर करने की उसकी सिद्ध क्षमता, ये सभी मिलकर उसे एक उच्च जोखिम वाला आरोपी बनाते हैं।इन परिस्थितियों में, इस समय उनकी रिहाई से निम्नलिखित का स्पष्ट और विश्वसनीय खतरा उत्पन्न होगा: दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़; प्रमुख साक्षी से बयान वापस लेने या उनके खिलाफ रुख अपनाने की साजिश रचना; फरार षड़यंत्रर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करना और घोटाले की रकम का पता लगाने में बाधा उत्पन्न करना।अन्वेषण से पहले ही यह खुलासा हो चुका है कि इस घोटाले के माध्यम से लगभग 4000 करोड़ रुपये की सार्वजनिक धनराशि का गबन किया गया है। आर्थिक अपराध की गंभीरता और सार्वजनिक हित पर इसका प्रभाव, विशेष रूप से संसाधन–सीमित राज्य में, जमानत देने के खिलाफ मजबूत कारक हैं, जैसा कि **गुलाबराव बाबूकर देवकर बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2013) 16 एससीसी 190** में रेखांकित किया गया है

50. दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़; प्रमुख साक्षी से खंडन या शत्रुतापूर्ण रुख अपनाना; फरार षड़यंत्रकर्ताओं के साथ समन्वय करना और घोटाले की रकम का पता लगाने में बाधा डालना।अन्वेषण से पहले ही यह खुलासा हो चुका है कि इस घोटाले के माध्यम से लगभग 4000 करोड़ रुपये की सार्वजनिक धनराशि का गबन किया गया है।आर्थिक अपराध की गंभीरता और सार्वजनिक हित पर इसका प्रभाव, विशेष रूप से संसाधन–सीमित राज्य में, जमानत देने के खिलाफ बाध्यकारी कारक हैं, जैसा कि गुलाबराव बाबुकर देवकर बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2013) 16 एससीसी 190 में रेखांकित किया गया है।

51. उत्तरवादी का निवेदन है कि आवेदक की शराब घोटाले में मुख्य षड्यंत्रकारी और वित्तीय सरगना के रूप में भूमिका के प्रथम दृष्टया पुख्ता सबूत मौजूद हैं; गवाहों को धमकाने और सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा वास्तविक, स्थापित और निरंतर बना हुआ है; और अपराध की गंभीरता, व्यापकता और सामाजिक प्रभाव, आवेदक के प्रभाव और आचरण के साथ मिलकर, इस मामले को जमानत देने के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त बनाते हैं।अत: यह विनम्रतापूर्वक निवेदन किया जाता है कि न्याय और जनहित में, यह न्यायालय वर्तमान जमानत याचिका को खारिज करने और रायपुर स्थित माननीय विशेष न्यायालय (पी.सी. एक्ट) द्वारा दिनांक 08.10.2025 को पारित आदेश की पुष्टि करने की कृपा करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

52. औपचारिक रूप से संरचित, राजनीतिक रूप से संरक्षित शराब घोटाला (2018–2023)

1.1 अन्वेषण से अब निर्णायक रूप से पता चलता है कि 2018 और 2023 के बीच, तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के कार्यकाल के दौरान, छत्तीसगढ़ में एक औपचारिक रूप से संरचित, राजनीतिक रूप से संरक्षित, राज्यव्यापी शराब घोटाला किया गया था।यह योजना अलग–अलग कृत्यों की एक श्रृंखला नहीं थी, बल्कि एक सुसंगठित और केंद्रीय रूप से समन्वित आपराधिक गिरोह थी।

1.2 अभिलेख में मौजूद सामग्री से पता चलता है कि नौकरशाही अधिकारी, राजनीतिक प्रतिनिधि और चुनिंदा निजी व्यक्ति एक संगठित सिंडिकेट के सदस्यों के रूप में काम करते थे, जिनमें से प्रत्येक उत्पाद शुल्क श्रृंखला के विभिन्न चरणों में परिभाषित भूमिकाएँ निभाते थे – नीति निर्माण, निविदा, खरीद, होलोग्राम आपूर्ति, खुदरा संचालन, नकदी संग्रह तथा धनशोधन।

53. ये सभी प्रमुख व्यक्ति वर्तमान आवेदक के स्पष्ट अनुमोदन, ज्ञान और सहमति से घनिष्ठ समन्वय में कार्य करते थे, जो इस आपराधिक उद्यम के प्रमुख षड्यंत्रकारी और केंद्रीय कमान व्यक्तियों में से एक के रूप में उभरा है।

2.2.सह–षड्यंत्रकारियों की विशिष्ट संस्थागत भूमिकाएँ – आवेदक की स्थिति का संदर्भ देना।

54. अन्वेषण में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिकाओं की पहचान की गई है, जो बदले में आवेदक की केंद्रीयता को रेखांकित करती हैं:ए.श्रीमती सौम्या चौरसिया – प्रारंभ में पाटन में उप–मंडल अधिकारी (एसडीएम) के पद पर तैनात रहीं, बाद में भिलाई–चारोदा नगर निगम की आयुक्त बनीं;इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर पदोन्नत हुईं।सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण से

उनकी निकटता और रणनीतिक नियुक्तियों ने उन्हें गिरोह के संचालन को सक्षम बनाने, सुगम बनाने और संरक्षण प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बना दिया।श्री अनिल टुटेजा, आईएएस – तत्कालीन मुख्यमंत्री के करीबी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जिन्होंने घोटाले के सुचारू संचालन को संभव बनाने वाली प्रशासनिक चालों को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।विभागीय संरचनाओं तक उनकी नौकरशाही पहुंच और प्रभाव ने इस षड़यंत्र को काफी मजबूत कर दिया।

55. श्री अनवर ढेबर – एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति और एक प्रभावशाली कांग्रेस नेता, जिन्होंने सिंडिकेट के एक प्रमुख संचालक के रूप में कार्य किया और घोटाले से उत्पन्न अवैध नकदी के संचलन के लिए एक केंद्रीय चैनल के रूप में कार्य किया।

56. ये भूमिकाएँ दर्शाती हैं कि आवेदक एक एकीकृत नेटवर्क के शीर्ष पर कार्यरत था, और घोटाले को अंजाम देने और छिपाने के लिए मिलकर काम करने वाले नौकरशाही, राजनीतिक और निजी पक्षों पर पर्यवेक्षी नियंत्रण रखता था।एकत्रित सामग्री स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि आवेदक अत्यधिक प्रभावशाली, पर्याप्त वित्तीय शक्ति वाला और नौकरशाही एवं राजनीतिक हलकों में गहरे संबंध रखने वाला व्यक्ति है।उनका नेटवर्क निर्वाचित प्रतिनिधियों, वरिष्ठ सिविल सेवकों और उत्पाद शुल्क एवं प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त निजी मध्यस्थों तक फैला हुआ है।इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, जांच एजेंसी ने उचित रूप से यह आशंका जताई है कि इस स्तर पर उसकी रिहाई चल रही जांच की अखंडता के लिए एक गंभीर, तत्काल और ठोस खतरा पैदा करेगी।यह आशंका न तो अस्पष्ट है और न ही काल्पनिक; यह निम्नलिखित ठोस उदाहरणों पर आधारित है:प्रमुख साक्षी को धमकाना, उन पर दबाव डालना और प्रलोभन देना; नकदी परिवहन में शामिल सह–आरोपियों और कूरियरों को प्रभावित करने या निष्क्रिय करने के प्रयास; और साक्ष्य प्रक्रिया में बाधा डालने, उसे पटरी से उतारने और दूषित करने की आवेदक की स्पष्ट प्रवृत्ति।ऐसी परिस्थितियों में, गंभीर आर्थिक अपराधों और भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत से संबंधित स्थापित सिद्धांत (जिनमें गुलाबराव बाबूकर देवकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी बनाम सीबीआई मामले शामिल हैं) राज्य के इस तर्क का पूर्णतः समर्थन करते हैं कि साक्षी को डराने–धमकाने और साक्ष्य से छेड़छाड़ का खतरा वास्तविक और गंभीर दोनों है, और न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर अभिरक्षा आवश्यक है।

57. निरंतर अभिरक्षा का समग्र प्रभाव तथा आवश्यकता।दस्तावेजी, वित्तीय और कथन संबंधी साक्ष्यों के संचयी प्रभाव से यह स्पष्ट होता है कि:

आवेदक राज्यव्यापी भ्रष्टाचार के जाल के केंद्र में था और शीर्ष स्तर के कमांडरों में से एक के रूप में कार्य कर रहा था; उसने व्यक्तिगत रूप से वित्तीय संरचना की निगरानी की और अवैध आय के आवागमन, भंडारण और उपयोग को सुनिश्चित किया; और इस घोटाले के कारण राज्य के खजाने को लगभग ₹4000 करोड़ का अभूतपूर्व नुकसान हुआ है, जिससे जनहित, राजस्व अखंडता और संस्थागत विश्वसनीयता को गंभीर रूप से ठेस पहुंची है।ऐसे साक्ष्यों के आलोक में, वर्तमान मामले में जमानत के माध्यम से किसी भी प्रकार की रियायत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उचित नहीं है।इसके विपरीत, यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता है कि अन्वेषण बिना किसी हस्तक्षेप, धमकी या दबाव के अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंच सके।

58. उपरोक्त अतिरिक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही पहले दिए गए लिखित और मौखिक कथनों को भी ध्यान में रखते हुए, विनम्रतापूर्वक यह दोहराया जाता है कि:आवेदक की भूमिका मुख्य षड्यंत्रकारी और प्रमुख लाभार्थी की है, न कि एक मामूली भागीदार की; इस स्तर पर उसकी रिहाई से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और साक्षी को रिश्वत देने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे चल रही जांच गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएगी; और अपराध की गंभीरता, व्यापकता और संगठित प्रकृति, साथ ही आवेदक के प्रभाव और आचरण को देखते हुए, यह मामला जमानत देने के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है।अतः, अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन किया जाता है कि यह माननीय न्यायालय वर्तमान जमानत याचिका को अस्वीकार कर दे और रायपुर स्थित माननीय विशेष न्यायालय (पी.सी. एक्ट) द्वारा दिनांक 08.10.2025 को पारित आदेश की पुष्टि करे।

निष्कर्ष तथा उपसंहार :

59. आवेदक, प्रतिवादी–राज्य के विद्वान अधिवक्ता को कई बार स्थगित होने पर भी विस्तार से सुना गया। एफआईआर संख्या [04/2024], आरोपपत्र (मुख्य + 5 पूरक), साक्षी के बयान, जब्त किए गए दस्तावेज़ और रिकॉर्ड में रखे गए दस्तावेजों सहित सभी रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

60. अभियोजन पक्ष के विवरण से अवैध शराब उत्पादन, होलोग्राम जालसाजी, नीतिगत तोड़फोड़, पार्ट–बी के तहत धन की हेराफेरी और ₹4000 करोड़ के सरकारी खजाने की तबाही में शामिल एक परिष्कृत गिरोह का पर्दाफाश होता है – जिसे विट्ठलपुरम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और शिवम कंस्ट्रक्शंस जैसी फर्जी संस्थाओं के माध्यम से अंजाम दिया गया था।

61. यह प्रकरण है कि आवेदक कथित तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य में सक्रिय एक बड़े गिरोह में शामिल था। अभियोजन पक्ष का यह भी कहना है कि ये आरोप संबंधित अवधि के दौरान लिए गए कुछ लेन–देन और आधिकारिक निर्णयों से संबंधित हैं, जिनमें यह तर्क दिया गया है कि आवेदक, अन्य आरोपियों के साथ मिलकर, एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर कुछ निजी व्यक्तियों को अनुचित लाभ हुआ और सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।अन्वेषण के दौरान दर्ज किए गए बयानों और अन्वेषण एजेंसी द्वारा स्थापित कथित संबंधों के आधार पर ही आवेदक को आरोपी बनाया गया है।

62. विशेष रूप से, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में आवेदक का नाम नहीं है और न ही एफआईआर में कथित अपराध में आवेदक की कोई प्रत्यक्ष, विशिष्ट या स्पष्ट भूमिका बताई गई है।आवेदक के खिलाफ लगाए जाने वाले आरोपों के लिए साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन, साक्षीयों की परीक्षा और दस्तावेजी सामग्री की गहन छानबीन आवश्यक होगी, जो पूरी तरह से विचारण के दायरे में आती है।यह सर्वविदित है कि जमानत आवेदन पर विचार करने के चरण में इस तरह की कार्यवाही पूरी तरह से अस्वीकार्य है, क्योंकि जमानत की कार्यवाही को लघु–विचारण में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

63. पुलिस/ईओडब्ल्यू/एसीबी द्वारा अन्वेषण शुरू की गई और आवेदक को दिनांक 17.01.2024 की एफआईआर संख्या 04/2024 के संबंध में 24.09.2025 को गिरफ्तार किया गया था।जैसा कि सूचित किया गया है, अन्वेषण काफी हद तक पूरी हो चुकी है और आवेदक से अब अभिरक्षा में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री मुख्य रूप से दस्तावेजी प्रकृति की है और पहले से ही अन्वेषण एजेंसी की अभिरक्षा में है।

64. आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा अपराध संख्या 03/2024 में दायर की गई पहली आरोपपत्र में आवेदक को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था।इसके बाद भी, ईओडब्ल्यू ने पांच पूरक आरोपपत्र दायर किए, लेकिन इनमें से किसी भी आरोपपत्र में आवेदक को आरोपी के रूप में नहीं दिखाया गया या पेश नहीं किया गया।

65. पांच पूरक आरोपपत्र दायर करने के बाद भी, अन्वेषण एजेंसी ने लगातार आवेदक को आरोपी के रूप में पेश करने से परहेज किया।यह स्वीकार किया गया तथ्य है कि आवेदक के कब्जे से किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु – न तो धन, न संपत्ति और न ही कोई आपत्तिजनक वस्तु – बरामद नहीं की गई है।अभियोजन पक्ष ने यह आरोप नहीं लगाया है कि अपराध की कथित आय का एक पैसा भी ईओडब्ल्यू द्वारा वर्तमान आवेदक से बरामद किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

67. जैसा कि स्वयं अभियोजन पक्ष ने स्वीकार किया है, अन्वेषण लगभग पूरी हो चुकी है, और रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि इस स्तर पर आवेदक से अभिरक्षा में पूछताछ करना आवश्यक या उचित है।अतः, निरंतर कारावास से अन्वेषण का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है। दण्ड प्रकिया संहिता कि धारा 161 के तहत दर्ज गवाहों के बयान मुख्य रूप से सह–आरोपी त्रिलोक सिंह ढिल्लों के खिलाफ निर्देशित हैं और आवेदक को कथित संलिप्तता के आधार पर फंसाने का प्रयास किया जा रहा है।यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उक्त सह–आरोपी को उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है, जिससे समता का सिद्धांत वर्तमान आवेदक के पक्ष में स्पष्ट रूप से लागू होता है।

68. अभियोजन पक्ष ने सह–आरोपी लक्ष्मी नारायण बंसल के बयान पर भरोसा किया है। घोषित भगोड़े/सह–अभियुक्त के खिलाफ अनिश्चितकालीन/स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद, और जांच अधिकारी के समक्ष उसकी उपलब्धता के बावजूद, उसे न तो गिरफ्तार किया गया और न ही उसके खिलाफ कार्यवाही की गई, और बयान दर्ज करने के बाद उसे स्वतंत्र रूप से जाने दिया गया। विधि का ऐसा चयनात्मक प्रयोग स्पष्ट रूप से "चुनिंदा" दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो निष्पक्ष और तटस्थ अन्वेषण की अवधारणा के विपरीत है।

68. प्रकरण की व्यापकता ही विचारण से पहले लंबी अवधि तक कारावास की निरर्थकता को दर्शाती है। अभियोजन पक्ष के अपने बयान के अनुसार, इस मामले में 51 आरोपी व्यक्ति, 1110 गवाह और लगभग 990 दस्तावेज शामिल हैं जो हजारों पृष्ठों में फैले हुए हैं।कई आरोपियों के विरुद्ध अभी तक आरोप निर्धारित नहीं

किए गए हैं और अन्वेषण जारी बताई जा रही है।ऐसे परिस्थिति में विचारण के शीघ्र निराकरण की संभावना नगण्य है।इस प्रकार के मामले में लंबे समय तक कारावास, दोष सिद्ध होने से पहले ही सजा देने के समान होगा और यह स्पष्ट रूप से आवेदक के भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत शीघ्र सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

69. प्रक्रियात्मक खामियों को बढ़ाते हुए, ईओडब्ल्यू ने सक्षम न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना आगे की अन्वेषण और पूरक रिपोर्ट दाखिल करने की कार्यवाही की है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनय त्यागी, विनूभाई हरिभाई मालविया और रॉबर्ट एल. चोंथु @ आर.एल. चोंथु (उपरोक्त) में निर्धारित विधि के विपरीत है।

70. आवेदक के विरुद्ध लगाए जाने वाले आरोपों के लिए साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन, साक्षीयों के विशाल समूह की जांच और विपुल अभिलेखों की छानबीन की आवश्यकता होगी, एक ऐसा अभ्यास जो केवल विचारण के दौरान ही किया जा सकता है।यह सर्वविदित विधिक तथ्य है कि जमानत की कार्यवाही को लघु विचारण में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।सभी तथ्यों को समग्र रूप से देखने पर—एफआईआर में आवेदक का नाम न होना, पहले आरोप पत्र और उसके बाद पांच पूरक आरोप पत्र में लगातार आरोप न लगाया जाना, बरामदगी का अभाव, जांच का पूरा होना, समान स्थिति वाले सह–आरोपियों को जमानत मिलना, जांच एजेंसी की ओर से प्रक्रियात्मक चूक और एक लंबे विचारण की अनिवार्यता—यह न्यायालय आवेदक की स्वतंत्रता को और अधिक सीमित करने का कोई ठोस कारण नहीं पाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

71. यह ध्यान रखना तथा भी महत्वपूर्ण है कि अभियोजन पक्ष के अपने ही प्रकरण के अनुसार, पूरे शराब घोटाले के कथित मास्टरमाइंड और प्रमुख षड़यंत्रकर्ता अरुण पति त्रिपाठी, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनुराग द्विवेदी और अरविंद सिंह बताए जाते हैं, जिन पर आपराधिक षड़यंत्र रचने, उसे अंजाम देने और उसे क्रियान्वित करने का आरोप है, जिसमें गिरोह का गठन और अपराध की आय को राजनेताओं और सार्वजनिक अधिकारियों में वितरित करना शामिल है।यह तथ्य और भी महत्वपूर्ण है कि उसी शराब घोटाले में कथित तौर पर शामिल होने वाले और अभियोजन पक्ष द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए 29 आबकारी अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है।कथित षड़यंत्र को अंजाम देने में जिनकी कथित भूमिका अभिन्न थी, इतनी बड़ी संख्या में सार्वजनिक अधिकारियों को जमानत देना, आवेदक के समानता के दावे को स्पष्ट रूप से मजबूत करता है।यदि ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है जो आवेदक की भूमिका को उन अधिकारियों से अधिक गंभीर या अलग साबित करता हो जिन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, तो आवेदक को जेल में रखना पूरी तरह से अनुचित होगा और जमानत देने से संबंधित स्थापित सिद्धांतों के विपरीत होगा।

72. उपर्युक्त आधिकारिक निर्णयों को वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू करने पर यह स्पष्ट है कि:

(क) आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था;

(ख) मूल या पांच पूरक आरोपपत्रों में उसे कभी भी आरोपी के रूप में पेश नहीं किया गया;

(ग) ईओडब्ल्यू द्वारा उससे कोई वसूली नहीं की गई है;

(घ) उसकी कथित भूमिका, यदि कोई है, तो वह अधिक से अधिक व्युत्पन्न और सहयोगी है;सिंह ढिल्लों को शीर्ष न्यायालय पहले ही जमानत दे चुकी है।

74. आवेदक के विरुद्ध किसी भी विशिष्ट सामग्री के अभाव में, जमानत से इनकार करना शत्रुतापूर्ण भेदभाव के बराबर होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित समानता के सिद्धांत का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।

75. अतः, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि आवेदक ने न केवल तथ्यों के आधार पर बल्कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित बाध्यकारी संवैधानिक और पूर्ववर्ती आदेशों के आधार पर भी जमानत देने के लिए एक स्पष्ट और ठोस मामला प्रस्तुत किया है।

76. इस तथ्य के बावजूद कि इस मामले में श्री लक्ष्मी नारायण बंसल के खिलाफ विशेष न्यायालय द्वारा एक स्थायी वारंट/अनिश्चितकालीन वारंट जारी किया गया था और वह अन्वेषण जांच अधिकारी के पास उपलब्ध था, उसने सह–आरोपी एलएनबी का बयान केवल दर्ज किया, उसे गिरफ्तार नहीं किया और उसे भागने दिया, ऐसा करना विधि का गंभीर उल्लंघन है।अतः, यह न्यायालय राज्य के पुलिस महानिदेशक को इस मामले की जांच करने और राज्य भर के सभी पुलिस अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि भविष्य में इसी तरह के उल्लंघन न हों।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

77. अभिलेख पर रखे गए तथ्यों पर गहन विचार करने के बाद, और अन्वेषण की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय मामले की खूबियों में जाए बिना, इस विचार पर पहुंचा है कि आवेदक को निरंतर कारावास में रखने का अब कोई बाध्यकारी या न्यायसंगत कारण नहीं है।प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, आवेदक को जमानत पर रिहा करने से न्याय के उद्देश्यों की पर्याप्त रूप से रक्षा होगी।

81. तदनुसार, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है और इसे स्वीकार किया जाता है।यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदक को ₹1,00,000/– (केवल एक लाख रुपये) की राशि का व्यक्तिगत मुचलका और इतनी ही राशि के दो स्थानीय ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर, विद्वानविचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित कठोर शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए, ताकि विचारण का निष्पक्ष, सुचारू और शीघ्र संचालन सुनिश्चित किया जा सके:

(क) यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो वह उसे विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा;

(ख) आवेदक को अन्वेषण तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करना होगा;

(ग) वह प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा;

(घ) जमानत की अवधि के दौरान वह कोई भी अपराध नहीं करेगा; और

(ङ) आवासीय पते और/या मोबाइल नंबर में परिवर्तन होने की स्थिति में, इसकी सूचना संबंधित न्यायालय को शपथ पत्र के माध्यम से दी जाएगी।

(च) विचारण न्यायालय द्वारा लगाई गई कोई भी कठोर शर्तें।

उपरोक्त शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन पक्ष को जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर शीघ्रता से और योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा।

82. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ कठोरता से वर्तमान जमानत आवेदन के निर्णय तक ही सीमित हैं।इस आदेश में कही गई कोई भी बात प्रकरण के गुण–दोष पर राय की अभिव्यक्ति नहीं मानी जाएगी।माननीय विचारण न्यायालय इस प्रकरण की कार्यवाही स्वतंत्र रूप से और इस आदेश में दी गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित होकर करेगा।

83. इसमें कही गई कोई भी बात प्रकरण के गुण–दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं मानी जाएगी और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से कार्यवाही करेगी।

सही/–
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य*

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur